नई दिल्ली
बुधवार
11 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 68
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को बिहार दौरे को लेकर...पेज-05

DELHIN/2014/58158

श्रद्धा, अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक बनेगा...पेज-08

एक नजर

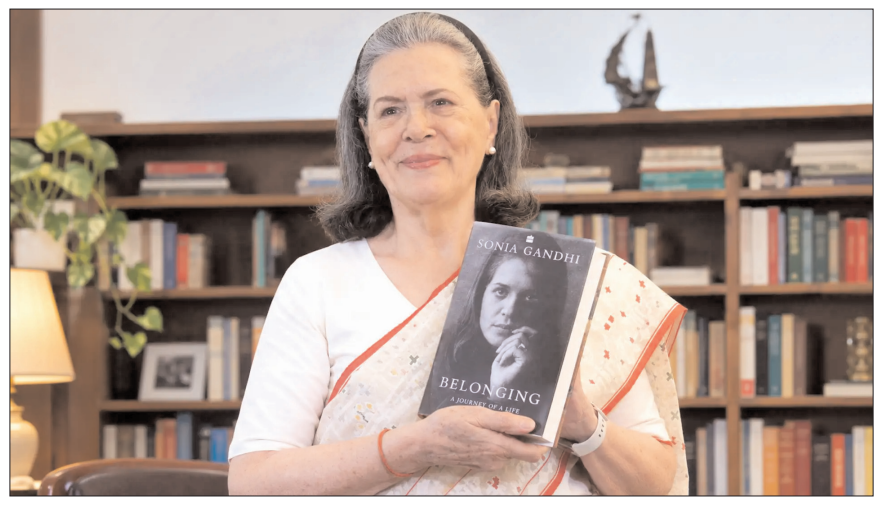
भारत की छवि धूमिल कर रहे चीनी इन्फ्लुएंसर्स पर कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका की झुग्गियों को 'नई दिल्ली' बताकर भारत की छवि धूमिल करने वाले चीनी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ संबंधित अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को नियमित पत्रकार वार्ता के दौरान इस हरकत को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि मनगढ़ंत प्रोपेगैंडा के जरिए किसी देश की गलत तस्वीर पेश करने से इसे बढ़ावा देने वालों की साख ही खत्म होती है। जायसवाल ने कहा, हमने इस संबंध में मीडिया रिपोर्टें देखी हैं। किसी भी देश की विकृत छवि प्रस्तुत करने के ऐसे प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जहां तक विदेशी तत्वों द्वारा ढाका के कुछ हिस्सों को नई दिल्ली के रूप में चित्रित करने के प्रयासों का सवाल है, झूठी कहानियों का प्रसार करने से इसमें शामिल लोगों और उनके पीछे के लोगों की विश्वसनीयता कम होती है। हम संबंधित अधिकारियों से उनके खिलाफ उचित कार्रवाई का आग्रह करते हैं। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 150 चीनी इन्फ्लुएंसर्स और लाइवस्ट्रीमर्स ढाका के उत्तर एवं टेकपारा जैसे गरीब इलाकों में वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। वे अपने चीनी दर्शकों को इन जगहों को भारत की राजधानी नई दिल्ली बताकर दिखा रहे हैं। ये चीनी नागरिक वीचैट और डौयिन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के रहन-सहन, स्वच्छता एवं बुनियादी ढांचे को लेकर अत्यंत आपत्तिजनक दावे कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वीडियो में स्थानीय चाय की दुकानों को दिखाकर गोमूत्र वाली चाय जैसे निराधार दावे भी किए गए। ये चीनी इन्फ्लुएंसर्स कम आय वाले क्षेत्रों में बिना अनुमति के लोगों के घरों के अंदर तक घुसकर वीडियो बना रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग भी उनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं।

दिल्ली-एनसीआर के कई क्षेत्रों में खतरनाक स्तर पर पहुंचा एक्यूआई

नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां के कई इलाकों में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) अत्यंत गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह से ही आसमान में छाई धुंध के कारण न सिर्फ दृश्यता घटी है, बल्कि आम लोगों को सांस लेने में भारी तकलीफ और आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में वायु गुणवत्ता रेड जोन (गंभीर श्रेणी) में पहुंच गई है। इनमें आईआईटी दिल्ली का एक्यूआई 388 (दिल्ली का सबसे प्रदूषित क्षेत्र), चांदनी चौक का एक्यूआई 380, आया नगर का 361, बुराड़ी क्रॉसिंग का 349, सिरीफोर्ट और पंजाबी बाग का क्रमशः 343-343, आरके पुरम का 338, गुरुग्राम का 323, मुंडका का 318, बदरपुर का 307, शादीपुर का 306, वजीरपुर का 304, आईजीआई एयरपोर्ट (टर्मिनल-3) और जहांगीरपुरी का क्रमशः 303-303 शामिल है। इसके अलावा विवेक विहार का 299, सोनिया विहार का एक्यूआई 283 दर्ज किया गया है जो गंभीर श्रेणी में है। प्रदूषण की मार केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी शहरों (एनसीआर) में भी हवा अत्यधिक जहरीली है।

सोनिया ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री नहीं बनने और निजी जीवन के कई प्रसंग किए साझा



नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' में अपने निजी जीवन, राजीव गांधी से मुलाकात और विवाह, भारत आने, परिवार की त्रासदियों तथा 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के फैसले से जुड़े कई प्रसंग साझा किए हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक पुस्तक के बजाय निजी संस्मरण बताया है और इसे राहुल, प्रियंका तथा अपने पोते-पोतियों रैहान और मिराया को समर्पित किया है। बिना किसी औपचारिक लोकार्पण कार्यक्रम के बाजार में आई इस किताब की मंगलवार से बिक्री भी शुरू हो गयी है। हार्पर कॉलिन्स इंडिया से प्रकाशित इस किताब में सात अध्याय हैं। इसके कवर पर लगी सोनिया गांधी की तस्वीर वर्ष 1966 में राजीव गांधी ने खींची थी।

सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को किताब का एक अंश साझा करते हुए 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के फैसले का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि उनके मन से संदेह के आखिरी अंश भी दूर हो गए थे और उन्होंने खुद से कहा कि उन्हें अपने प्रति सच्चा रहना चाहिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी एक्स पर किताब के प्रकाशन पर सोनिया गांधी को बधाई दी। उन्होंने उनके जीवन को प्रेरणादायक यात्रा बताते हुए कहा कि उनके साथ काम करना और उनके नेतृत्व को करीब से देखना उनके लिए विशेष अनुभव रहा है। सोनिया गांधी ने किताब में बताया है कि उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही तय कर लिया था कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर वह प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगी। राहुल और प्रियंका भी उन्हें इस पद पर नहीं देखना चाहते थे। उन्हें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं की यादें थीं और आशंका थी कि प्रधानमंत्री बनने से सोनिया की जान को खतरा बढ़ सकता है। सोनिया ने लिखा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपना फैसला सार्वजनिक नहीं किया, ताकि पार्टी में नेतृत्व को लेकर विवाद न हो। चुनाव जीतने के बाद गठबंधन के नेताओं ने उन्हें फैसला बदलने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी असहमति जताई, लेकिन नेताओं ने उनकी बात पूरी सुने बिना ही इसे सहमति मान लिया। इस दौरान राहुल ने उनसे पूछा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए हां क्यों कहा। प्रियंका ने भी उन्हें याद दिलाया कि वह पहले ही अपना फैसला स्पष्ट कर चुकी थीं। सोनिया ने प्रधानमंत्री नहीं बनने के पीछे विदेशी मूल के मुद्दे को भी एक वजह बताया। उन्हें आशंका थी कि उनके प्रधानमंत्री बनने पर भाजपा और उसके सहयोगी दल इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकते हैं। अंततः उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया। किताब में सोनिया ने राजीव गांधी से पहली मुलाकात का भी जिक्र किया है। वह 19 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी सीखने इटली से कैम्ब्रिज पहुंची थीं। वहां एक ग्रीक रेस्तरां में उनकी नजर राजीव गांधी पर पड़ी। जनवरी के एक दिन उनके दोस्त क्रिश्चियन वॉन स्टिगलिट्ज ने दोनों की मुलाकात कराई। सोनिया ने किताब में बताया कि उनकी पहली मुलाकात में ही दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे। धीरे-धीरे मुलाकातें बढ़ीं और दोनों ने साथ समय बिताना शुरू किया। वह अपने रिश्ते के बारे में पिता को बताने से डरती थीं, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि पिता उन्हें इटली वापस बुला लेंगे। सोनिया ने इटली की नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिकता लेने पर लिखा कि लंबे समय तक उन्होंने अपना इटली का पासपोर्ट संभालकर रखा था, क्योंकि वह उनकी पहचान का हिस्सा था। राजीव गांधी के सार्वजनिक जीवन में आने के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता लेना सही लगा। वर्ष 1983 में भारतीय नागरिकता लेने की औपचारिक प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज पढ़ते समय उनकी धड़कन तेज हो गई थी। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पहचान का एक हिस्सा हमेशा के लिए छूट रहा है। किताब में अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ मुलाकातों के कई रोचक प्रसंग भी हैं। सोनिया ने वर्ष 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा का जिक्र करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने क्लिंटन को वहां मौजूद खूबसूरत महिलाओं को चोरी-छिपे देखते हुए पाया था। उन्होंने क्लिंटन के कश्मीर संबंधी विचारों का भी उल्लेख किया है। सोनिया ने किताब में बताया कि क्लिंटन कश्मीर को परमाणु टकराव का केंद्र और दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानते थे।

सोनिया गांधी के दावों पर एच.एस. फुल्का ने उठाए सवाल

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं एडवोकेट एच.एस. फुल्का ने 1984 के सिख विरोधी कत्लेआम को लेकर सोनिया गांधी की किताब में किए गए दावों पर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए फुल्का ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में राजीव गांधी और अपने परिवार को क्लीन चिट देने का प्रयास किया है, जबकि उनके दावे मिश्रा आयोग और नानावती आयोग की रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों के विपरीत हैं। फुल्का ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में दावा किया है कि 31 अक्टूबर 1984 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सेना प्रमुख जनरल वैद्य को सेना बुलाने के लिए कहा था। इसके बाद जनरल वैद्य ने दिल्ली के आसपास मौजूद सिख सैनिकों को नहीं बुलाने का निर्णय लिया और देहरादून सहित अन्य दूरस्थ स्थानों से सेना बुलाने का फैसला किया, जिससे सेना की तैनाती में देरी हुई।

उन्होंने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि सेना प्रमुख जनरल वैद्य ने सिख सैनिकों पर अविश्वास के कारण सेना नहीं बुलाने का फैसला नहीं किया था। फुल्का के अनुसार, 31 अक्टूबर की रात और 1 नवंबर की सुबह दिल्ली में लगभग 6,100 सैनिक उपलब्ध थे, लेकिन उन्हें समय पर तैनात नहीं किया गया। एच.एस. फुल्का ने मिश्रा आयोग और नानावती आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यदि 1 नवंबर 1984 की सुबह दिल्ली में उपलब्ध 5,000 सैनिकों को सड़कों पर तैनात किया जाता, तो कम से कम 2,000 सिखों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वैद्य ने मिश्रा आयोग के समक्ष अपने बयान में स्पष्ट किया था कि उन्होंने दिल्ली में सेना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जीओसी दिल्ली से संपर्क किया था। उन्हें बताया गया था कि दिल्ली में लगभग 6,000 सैनिक उपलब्ध हैं। इसके अलावा मेरठ से भी सेना बुला ली गई थी, जो 31 अक्टूबर की रात दिल्ली पहुंच गई थी। फुल्का ने कहा कि जनरल वैद्य ने अपने बयान में यह नहीं कहा था कि राजीव गांधी या तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें सेना बुलाने का निर्देश दिया था। मिश्रा आयोग के अनुसार, राजीव गांधी ने जनरल वैद्य को अलर्ट किया था, लेकिन सेना को तैयार रखना और उसे नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर तैनात करना अलग-अलग जिम्मेदारियां थीं। भाजपा नेता ने कहा कि सेना की तैनाती की जिम्मेदारी नागरिक प्रशासन की थी। इसके बावजूद दिल्ली में उपलब्ध सेना को समय रहते न तो बुलाया गया और न ही तैनात किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और दिल्ली में हजारों सैनिक उपलब्ध थे, तो उन्हें तैनात क्यों नहीं किया गया?

- कहा- अगर समय पर सैनिकों को सड़कों पर उतारा जाता तो बचाई जा सकती थी 2,000 सिखों की जान



दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार

नई दिल्ली,एजेंसी। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखा जा रहा है। एक तरफ उत्तर भारत में दिन-ब-दिन कोहरे के साथ ठंड बढ़ रही है वहीं दक्षिण के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और आंधी-तूफान के आसार हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार 13 नवंबर को दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो अगले 24 घंटों में और मजबूत होकर स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। दिल्ली-एनसीआर में आने वाले दिनों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिलेगा। 11-13 नवंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम बदलने के आसार हैं। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में 13 तारीख तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

विशेष रूप से 12 नवंबर को कश्मीर घाटी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 12-16 नवंबर के दौरान पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 11-14 नवंबर के दौरान जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। दक्षिण भारत के दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के चलते प्रायद्वीपीय भारत में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 11, 15 एवं 16 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। केरल और माहे में 11-15 नवंबर तक बारिश जारी रहेगी जबकि 16 नवंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

कांग्रेस हैदराबाद में 13-14 नवंबर को करेगी भारत समिट, 70 देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली। कांग्रेस 13 एवं 14 नवंबर को हैदराबाद में भारत समिट आयोजित करेगी। इसमें 70 देशों के करीब एक हजार प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें नीति निर्माता और दुनिया के विभिन्न देशों के प्रगतिशील आंदोलनों से जुड़े प्रमुख नेता शामिल होंगे। समिट में नए वैश्विक व्यवस्था, भू-राजनीतिक बदलाव, जलवायु परिवर्तन, मीडिया की भूमिका और सूचना की विश्वसनीयता सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। पूर्व विदेश मंत्री, कांग्रेस के विदेश विभाग के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि यह समिट दो महत्वपूर्ण अवसरों के साथ आयोजित हो रही है। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती और भारत की आजादी के 80 वर्ष पूरे होना शामिल है। उन्होंने कहा कि नेहरू की सोच आज भी कांग्रेस की विदेश नीति और उसके दृष्टिकोण के लिए प्रेरणा है।

गृह मंत्रालय के विशेष अभियान-6 में 11,902 जन शिकायतों और 1,666 अपीलों का निपटारा

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लंबित मामलों के निपटारे, कार्यालयों में स्वच्छता और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष अभियान-6 के तहत 11,902 जन शिकायतों और 1,666 अपीलों का निपटारा किया है। एक महीने तक चले इस अभियान के दौरान 78,125 वर्ग फुट कार्यालयी स्थान खाली कराया गया और कबाड़ के निस्तारण से 10.17 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि विशेष अभियान-6 दो से 31 अक्टूबर तक चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों का निपटारा, स्वच्छता को बढ़ावा देना, कार्यालय प्रबंधन में सुधार और आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना था। इस दौरान विशेष रूप से उन क्षेत्रीय और दूरस्थ कार्यालयों पर ध्यान दिया गया, जिनका आम जनता से सीधा संपर्क रहता है।



मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत सांसदों से प्राप्त 147 संदर्भों और राज्य सरकारों से मिले 141 संदर्भों का भी निपटारा किया गया। इसके अलावा 2,19,644 भौतिक फाइलों और 30,385 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा की गई। पुराने और अनुपयोगी अभिलेखों के निस्तारण तथा बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन के जरिये 78,125 वर्ग फुट कार्यालयी जगह खाली कराई गई। स्वच्छता अभियान के लिए शुरुआत में 6,757 स्थलों की पहचान की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 7,963 कर दिया गया। कबाड़ के निस्तारण से 10.17 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई, जिसमें 2.63 करोड़ रुपये ई-कचरे के निस्तारण से मिले। मंत्रालय ने बताया कि अभियान के तहत 13 अक्टूबर को एक दिवसीय विशेष गहन अभियान भी चलाया गया। इसमें पौधरोपण, व्यापक स्वच्छता अभियान और पुराने तथा अनुपयोगी अभिलेखों को हटाने जैसी गतिविधियां संचालित की गईं। अभियान में मंत्रालय के सभी विभागों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और संबद्ध संगठनों ने सक्रिय भागीदारी की। अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर #SpecialCampaign6 हैशटैग के साथ करीब 1,200 पोस्ट साझा की गईं। इनमें एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि विशेष अभियान-6 से न केवल कार्यालयों में स्वच्छता और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिली है, बल्कि प्रशासनिक कामकाज में जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता की संस्कृति को भी मजबूती मिली है। मंत्रालय ने भविष्य में भी प्रभावी जनसेवा, जवाबदेही, स्वच्छता और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत चालू वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ डॉलर का निर्यात लक्ष्य पाने की राह पर: गोयल

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को भरोसा जताया कि भारत चालू वित्त वर्ष 2026-27 में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात का एक लाख करोड़ डॉलर का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

गोयल ने 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027' के कर्टेन रेजर (शुरुआती कार्यक्रम) को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में ही देश का कुल निर्यात 480 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो निर्धारित सालाना लक्ष्य का 48 फीसदी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027' के संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए



कहा, 'हम निर्यात लक्ष्य का 48 फीसदी हासिल कर चुके हैं... हम लक्ष्य हासिल करने की राह पर हैं। यह लक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण है और हमें इसे हासिल करना है।

उन्होंने वाहन उद्योग से घरेलू बाजार के साथ वैश्विक बाजारों पर भी ध्यान देने और निर्यात बढ़ाने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027' का तीसरा संस्करण 4 से 9 फरवरी, 2027 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

यमुना में शुरू हुई दिल्ली की पहली रिवर क्रूज सेवा

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली में यमुना नदी पर पहली मनोरंजक क्रूज सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में सोनिया विहार-जगतपुर खंड पर इस सेवा का उद्घाटन किया। 30 यात्रियों की क्षमता वाला इलेक्ट्रिक क्रूज करीब छह किलोमीटर के क्षेत्र में नदी की सैर कराएगा। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में नदी पर्यटन को बढ़ावा देना और यमुना को पर्यटन एवं मनोरंजन के नए केंद्र के रूप में विकसित करना है।

कार्यक्रम में केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के लोक निर्माण और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, वन एवं पर्यावरण और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा तथा सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव विजय कुमार, दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील कुमार लोहानी सहित केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की नदियां और अंतर्देशीय जलमार्ग आर्थिक विकास, पर्यटन और टिकाऊ संपर्क के महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। यमुना पर क्रूज सेवा की शुरुआत दिल्ली में नदी पर्यटन की नई लहर का संकेत है।

सरकार नदियों की क्षमता का उपयोग पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना दिल्ली के इतिहास, संस्कृति और पहचान का अभिन्न हिस्सा है। क्रूज सेवा से दिल्ली के निवासियों और पर्यटकों को नदी को नए तरीके से देखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना के किनारे को बेहतर सुविधाओं और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के साथ आकर्षक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस परियोजना को व्यापक पर्यटन और मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहां संगीतमय फव्वारे के साथ रोशनी और ध्वनि का विशेष कार्यक्रम होगा। इसमें यमुना के इतिहास और धार्मिक महत्व को दर्शाया जाएगा। इसमें सूर्य देव, यम और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं के साथ कालिया दमन की कथा भी दिखाई जाएगी। परियोजना में खानपान केंद्र, खरीदारी क्षेत्र, बच्चों के खेलने की जगह और स्केटिंग तथा रॉक क्लाइंबिंग जैसी साहसिक गतिविधियों की सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। इसके अलावा तैरते हुए जेटी, टिकट काउंटर, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, शौचालय, प्रतीक्षालय और रोशनी से युक्त पहुंच मार्ग बनाए गए हैं।

- 30 यात्रियों की क्षमता वाला इलेक्ट्रिक जहाज चलेगा



दीपावली के मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के 141.88 करोड़ रुपये 15 लाख लाभार्थियों के खातों में भेजे गए

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 15 लाख से अधिक पात्र राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि भेजी। लाभार्थियों को सांकेतिक चेक भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर दिल्ली के खाद्य-आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, कुलदीप सोलंकी, चंदन चौधरी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने घोषित संकल्पों को पूरा करने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राशन कार्डधारक परिवारों को होली और दीपावली पर आर्थिक सहायता देने की योजना इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। सहायता राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित करने से लाभार्थियों तक आर्थिक सहयोग पहुंचाने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनती है।



उन्होंने बताया कि सरकार ने राशन कार्डधारक परिवारों को होली और दीपावली पर एलपीजी सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई थी। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष दीपावली के अवसर पर दिल्ली के 15,45,994 परिवारों के बैंक खातों में कुल 141.88 करोड़ रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1,24,964 परिवार और नॉन पीएमयूवाई श्रेणी के 14,21,030 परिवार शामिल हैं। इनमें पीएमयूवाई श्रेणी के प्रत्येक परिवार को 642 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं नॉन पीएमयूवाई श्रेणी के प्रत्येक परिवार को 942 रुपये की सहायता राशि दी गई। इसका उद्देश्य वर्ष में दो प्रमुख त्योहारों पर परिवारों को आर्थिक सहयोग देना और घरेलू खर्च का बोझ कम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने योजना के अंतर्गत सहायता राशि हस्तांतरित करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था अपनाई है। इसके माध्यम से राशि परिवार के मुखिया के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे पहुंचाई जाती है। उन्होंने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन में लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड संबंधी विवरणों का सत्यापन और आवश्यक डेटा का मिलान किया जाता है, ताकि निर्धारित पात्र परिवारों तक सहायता पहुंच सके। साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने और किसी प्रकार की दोहरी सहायता, राशि के दुरुपयोग या अनियमितता को रोकने के लिए निगरानी एवं ऑडिट की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली केवल रोशनी और उत्सव का पर्व नहीं, बल्कि खुशियां साझा करने और एक-दूसरे के जीवन में सहयोग देने का अवसर भी है। सरकार की यह पहल दिल्ली के राशन कार्डधारक परिवारों को त्योहारों पर आर्थिक सहयोग प्रदान करने और उनके जीवन में खुशियां बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दीपावली और भाई दूज के पावन अवसर पर तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक पात्र राशन कार्डधारक परिवारों के बैंक खातों में लगभग 142 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी से भेजी गई। इससे पहले होली के अवसर पर भी पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया था। हमारा उद्देश्य केवल त्योहारों पर आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महंगाई के इस दौर में परिवारों के घरेलू खर्च को कम करना, माताओं-बहनों की बचत बढ़ाना और उनके जीवन में आर्थिक राहत एवं खुशहाली लाना है।

उपराज्यपाल ने लोधी गार्डन में बागवानी से जुड़ी विभिन्न पहलों का लिया जायजा

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को लोधी गार्डन में दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की नर्सरी का दौरा किया। उन्होंने वहां बागवानी से जुड़ी विभिन्न पहलों का जायजा लिया। इसमें हाई-टेक नर्सरी, ट्यूलिप ग्रोथ-कम-स्टोरेज चैंबर, कम्पोस्टिंग सुविधाएं, कैक्टस हाउस और 'ट्री एम्बुलेंस' शामिल हैं। उपराज्यपाल ने एनडीएमसी को ट्यूलिप उगाने की एक स्वदेशी प्रक्रिया विकसित करने, मौसमी फूलों का दायरा बढ़ाने और स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने स्थानीय ट्यूलिप की खेती को बढ़ावा देने, बागवानी क्षमताओं को मजबूत करने और शहर के हरित क्षेत्रों को संरक्षित करने की दिशा में एनडीएमसी के प्रयासों की भी सराहना की। इस दौरे के दौरान एनडीएमसी अध्यक्ष एम के द्विवेदी, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल और परिषद के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।



इस अवसर ने बागवानी में नवाचार, टिकाऊ हरित प्रथाओं और नई दिल्ली को अधिक स्वच्छ, हरित और सुंदर बनाने के प्रति एनडीएमसी की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। इससे पहले उपराज्यपाल ने आज कड़कड़डूमा में 'ईस्ट दिल्ली हब' के एकीकृत विकास की समीक्षा की। इस दौरान विधायक ओपी शर्मा, वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर भी मौजूद रहे। उन्होंने यहां सार्वजनिक परिवहन संपर्क को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत आवासीय टावरों, नागरिक सुविधाओं और हरित क्षेत्रों के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी एबीसीसी को निर्देश दिए कि वे आपसी तालमेल बेहतर रखें, लंबित कानूनी मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाएं और समय पर प्रोजेक्ट पूरा करके इसे सौंपें। उन्होंने पूर्वी दिल्ली, टिकाऊ और सुव्यवस्थित शहरी जीवन का एक बेहतरीन उदाहरण बनेगी। प्रोजेक्ट का परिणाम, तय किए गए विजन के अनुरूप ही होना चाहिए। यह विकसित दिल्ली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दिवाली पर पटाखों से झुलसने के 197 मामले, सफदरजंग अस्पताल में पहुंचे 206 मरीज

नई दिल्ली। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल में दिवाली के दौरान आग से झुलसने के कुल 206 मामले सामने आए हैं। अस्पताल के अनुसार, 7 से 9 नवंबर 2026 के बीच तीन दिनों में 206 लोग जलने की चोटों के कारण अस्पताल पहुंचे।



अस्पताल के बर्न्स, प्लास्टिक एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग की प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉ. सुजाता सरबाही ने बताया कि इस वर्ष भी पिछले सालों की तरह ही झुलसने के मामले सामने आए हैं। डॉ. सुजाता सरबाही के अनुसार, दिवाली से एक दिन पहले, दिवाली के दिन और उसके अगले दिन यानी तीन दिनों में विभाग में दिवाली से संबंधित जलने की चोटों के 206 मरीज आए। इनमें से 197 मामले पटाखों के कारण हुए, जबकि नौ मरीज तेल के दीयों (दीये) से झुलसे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मरीजों की संख्या पिछले वर्षों के समान रही है। दिवाली के दौरान पटाखों से होने वाली दुर्घटनाएं जलने की चोटों का प्रमुख कारण बनी रहीं।

गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संदेश देती है : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश दक्षिण दिल्ली में पारंपरिक विधि-विधान से गोवर्धन पूजा की और भगवान श्रीकृष्ण के समक्ष शीश नवाकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा भक्ति, विनम्रता, कृतज्ञता और प्रकृति के प्रति श्रद्धा जैसे शाश्वत मूल्यों का प्रतीक है। यह पर्व मानवता को प्राकृतिक पर्यावरण के सम्मान एवं संरक्षण के अपने दायित्व का स्मरण कराता है तथा अपनी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है।

मंदिर प्रवास के दौरान विजेंद्र गुप्ता ने मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों एवं अन्नकूट उत्सव में भाग लिया, भगवान को अर्पित किए गए भव्य भोग के दर्शन किए तथा भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने पारंपरिक पूजा-अर्चना एवं भक्तिमय अनुष्ठानों के माध्यम से अपनी



श्रद्धा अर्पित की और श्रद्धालुओं के साथ इस पावन अवसर के उत्सव में सहभागिता की। अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे पर्व आस्था, सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता के बंधनों को सुदृढ़ करते हैं तथा लोगों को करुणा, सद्भाव और निःस्वार्थ सेवा के मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर विजेंद्र गुप्ता ने इस्कॉन कम्युनिकेशंस के निदेशक बृज नंदन दास को दिल्ली विधानसभा की आधिकारिक पत्रिका 'विधान चेतना' भेंट की। यह पहल आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ विधानसभा के विधायी, सांस्कृतिक और बौद्धिक योगदान को साझा करने के महत्व को दर्शाती है। अध्यक्ष ने मंदिर के पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं से भी संवाद किया तथा आध्यात्मिक परंपराओं के संरक्षण और भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाओं एवं दर्शन के प्रचार-प्रसार के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष ने गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर समस्त दिल्लीवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि यह पर्व प्रत्येक परिवार के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाएं आज भी समाज को धर्म, कर्तव्य, भक्ति और सामूहिक कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं तथा उनकी प्रासंगिकता युगों-युगों से बनी हुई है।

हर्ष मल्होत्रा ने सोनिया की पुस्तक में 'ब्लूस्टार' के संदर्भ पर जताई आपत्ति, कहा सिख समाज से माफी मांगे

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की पुस्तक में ब्लूस्टार के संदर्भ की आलोचना की है। मल्होत्रा का कहना है कि इसमें उन्होंने लिखा है कि ऑपरेशन के बाद स्वर्ण मंदिर साहिब और अकाल तख्त साहिब की तस्वीरें देखकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व्यथित हो गई थीं। यह कथन तथ्यों से परे और सिख समाज के घावों पर नमक छिड़कने वाला है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' पर एक वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने कहा कि सिखों की सर्वोच्च आस्था के केंद्र स्वर्ण मंदिर साहिब अमृतसर पर हमला इंदिरा गांधी के आदेश पर ही हुआ था। ऐसे में उनके व्यथित होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उन्हें पहले से पता रहा होगा कि क्या परिणाम होंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि असल में व्यथित सिख समाज था। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 1984 के बीच कांग्रेस के संरक्षण में सिखों के पूजा स्थलों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चुन-चुन कर निशाना बनाया गया। हजारों निर्दोष सिखों का नरसंहार हुआ। हर्ष मल्होत्रा ने सोनिया गांधी से 1984 में हुए सिख नरसंहार के लिए सिख समाज और उसकी आने वाली पीढ़ियों से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की।

महापौर ने मल्कागंज वार्ड का किया निरीक्षण, अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के दिये आदेश

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने मंगलवार को उत्तरी क्षेत्र में स्थित मल्कागंज वार्ड की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर प्रवेश वाही ने लगभग दो किलोमीटर चलकर मल्कागंज वार्ड की मुख्य सड़क पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रवेश वाही ने मल्कागंज चौक पर स्थित पार्क से स्वयं मलबा हटाया एवं मुख्य मार्ग की जेटिंग मशीन से सफाई की। उन्होंने मल्कागंज मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण की स्थिति पर नाराजगी जताई और इसे तुरंत हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिक्रमण करने वालों के चालान करने के आदेश दिए।

उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महापौर ने एक स्वच्छता कर्मी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया एवं उसका नाम पुरस्कार के लिए भेजने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि बिना जनभागीदारी के यह कार्य संभव नहीं है। उन्होंने दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए जनता का सहयोग मांगा। साथ ही, महापौर ने तिमारपुर में स्थित बालकराम अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन एवं सीरम की प्रचुर उपलब्धता पर संतोष व्यक्त किया और लैब का भी निरीक्षण किया। महापौर ने अस्पताल में आए रोगियों से बातचीत कर डाक्टरों एवं दवाओं की उपलब्धता के बारे में



जानकारी ली। मुख्य सड़क से अस्पताल की अप्रोच रोड बनाने के कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निगम अपने अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के दौरान तिमारपुर के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री, स्थानीय पार्षद रेखा, अतिरिक्त आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल, उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त सचिन गुप्ता, अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ पूनम सरीन सहित दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पांच वर्षों में नए एम्स में पूरे किए 6 करोड़ से अधिक ओपीडी परामर्श

नई दिल्ली। देशभर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत स्थापित नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में पिछले पांच वर्षों के दौरान 6 करोड़ से अधिक ओपीडी परामर्श दर्ज किए गए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 तक सभी एम्स में कुल 6.01 करोड़ ओपीडी परामर्श हो चुके हैं। यह उपलब्धि देश में विशेषज्ञ और उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती पहुंच को दर्शाती है।

मंत्रालय ने की तरफ से जारी जानकारी में बताया गया है कि पीएमएसएसवाई के तहत विभिन्न चरणों में कुल 22 नए एम्स स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 18 पूरी तरह से संचालित हो रहे हैं। ये संस्थान बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी), भर्ती रोगी विभाग (आईपीडी), आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेवाएं, जांच सुविधाएं, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान जैसी व्यापक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नए एम्स में ओपीडी परामर्श की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 में जहां 50.03 लाख ओपीडी परामर्श हुए थे, वहीं 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 77.95 लाख और 2023-24 में 100.52 लाख हो गई। वर्ष 2024-25 में 129.98 लाख तथा 2025-26 में 144.96 लाख ओपीडी परामर्श दर्ज किए गए। वित्त वर्ष 2026-27 में अक्टूबर 2026 तक नए एम्स में 97.41 लाख ओपीडी मरीजों ने परामर्श लिया। मंत्रालय ने बताया कि नए एम्स में स्नातक, स्नातकोत्तर और नर्सिंग शिक्षा के अवसरों का भी विस्तार किया गया है। इसके साथ ही विशेष क्लीनिकल सुविधाओं और उन्नत चिकित्सा सेवाओं का विकास किया जा रहा है। सरकार की यह पहल देश में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

दिल्ली में प्रदूषण पर आआपा का सरकार पर निशाना, कहा- जनता को स्वच्छ हवा देना सरकार की जिम्मेदारी



नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी (आआपा) ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में नेता प्रतिपक्ष और आआपा नेता अंकुश नारंग ने मंगलवार को सिविक सेंटर में आयोजित पत्रकार को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है। दिवाली की रात पटेल नगर में एक्यूआई 1870 तक पहुंचने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 500 के पार दर्ज किया जा रहा है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और अस्थमा व अन्य सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।

नारंग ने कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी को प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि सड़कों पर पानी का छिड़काव, धूल नियंत्रण और प्रदूषण कम करने के लिए प्रभावी इंतजाम पर्याप्त रूप से क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। नारंग ने वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जहांगीरपुरी के एक मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी का छिड़काव किए जाने से आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने दिवाली के दिन कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों के बंद रहने का मुद्दा उठाते हुए इसकी जांच कराने और प्रदूषण के वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। आआपा नेता ने कहा कि प्रदूषण का सीधा असर दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एमसीडी को मिलकर तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई करने की भी मांग की। अंकुश नारंग ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव, धूल प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। साफ हवा दिल्लीवासियों का अधिकार है और सरकार को इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए।

एमसीडी की आय बढ़ाने के लिए एआई का सहारा, 180 दिन के पायलट प्रोजेक्ट से होगी विज्ञापन स्थलों की डिजिटल मैपिंग

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और राजस्व के नए स्रोत विकसित करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और आधुनिक तकनीक का सहारा लेगा। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने मंगलवार को जानकारी दी कि आउटडोर विज्ञापन व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए 180 दिन का पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके तहत दिल्ली में होर्डिंग, यूनिपोल, कियोस्क और स्ट्रीट फर्नीचर सहित सभी आउटडोर विज्ञापन स्थलों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी।

सत्या शर्मा ने कहा कि एमसीडी के पास राजस्व अर्जित करने के कई संसाधन हैं, लेकिन उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। विज्ञापन क्षेत्र में एआई, जीआईएस मैपिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग के इस्तेमाल से न केवल आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि राजस्व के नुकसान को रोकने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए आर3 इंटरएक्टिव मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 180 दिन के पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत निजी एजेंसी अपने खर्च पर विज्ञापन परिसंपत्तियों का सर्वे, जियो-टैगिंग और जीआईएस आधारित मैपिंग करेगी। खास बात यह है कि इस परियोजना पर एमसीडी को कोई वित्तीय खर्च नहीं करना होगा। प्रस्ताव को स्थायी समिति के माध्यम से निगम की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है। एमओयू के मसौदे में निगम के विधि एवं वित्त विभाग के सुझाव भी शामिल किए गए हैं। इस परियोजना में एजेंसी के एआई आधारित विजुअल लोड इंडेक्स (वीएलआई) टूल की अहम भूमिका होगी। यह टूल सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे विज्ञापनों की संख्या, दृश्यता और उनसे पैदा होने वाली दृश्य अव्यवस्था का विश्लेषण करेगा। इसके आधार पर ऐसे स्थानों और विज्ञापन कॉरिडोर की पहचान की जाएगी, जहां विज्ञापन लगाने की अधिक व्यावसायिक संभावनाएं मौजूद हैं। वहीं, जिन इलाकों में विज्ञापनों की अधिकता है, वहां उनकी संख्या और स्थान को व्यवस्थित करने के सुझाव भी मिलेंगे। इससे निगम को विज्ञापन स्थलों की नीलामी, मूल्यांकन और टेंडर प्रक्रिया की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।

परियोजना के तहत 360 डिग्री वर्चुअल सर्वे के जरिए प्रत्येक विज्ञापन स्थल की तस्वीरें, लोकेशन, आकार, रोशनी और नियमों के अनुपालन से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। जीआईएस मैपिंग और जियो-टैगिंग के माध्यम से सभी विज्ञापन परिसंपत्तियों का केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा। इसके अलावा डैशबोर्ड, हीट मैप और एनालिटिक्स रिपोर्ट के जरिए विज्ञापन स्थलों की निगरानी और प्रबंधन किया जा सकेगा। डिजिटल डेटाबेस का पंजीकृत विज्ञापन स्थलों के रिकॉर्ड से मिलान कर अनधिकृत विज्ञापन संरचनाओं की पहचान की जाएगी। इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान होगा और निगम को होने वाले राजस्व नुकसान पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। सत्या शर्मा ने बताया कि एमओयू के तहत सर्वे से जुटाया गया पूरा डाटा



एमसीडी की संपत्ति रहेगा। निजी एजेंसी निगम की लिखित अनुमति के बिना इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं कर सकेगी। समझौता हस्ताक्षर होने के बाद 180 दिन तक प्रभावी रहेगा। शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में निगम 15 दिन का नोटिस देकर समझौता समाप्त कर सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पायलट प्रोजेक्ट एमसीडी की विज्ञापन व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और राजस्वोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना के नतीजों का मूल्यांकन करने के बाद इसे अन्य जोन और पूरे दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।

एक नजर

बाइक के 67 चालान व चार लाख लाख से ज्यादा जुर्माना, जब्त

गुरुग्राम,एजेंसी। बार-बार यातायात नियम तोड़ने वालों पर गुरुग्राम यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए एक ऐसी मोटरसाइकिल को इम्पाउंड किया है, जिस पर कुल 67 चालान लंबित थे। इन चालानों की बकाया जुर्माना राशि चार लाख छह हजार 500 रुपये है। जानकारी के अनुसार, जोनल अधिकारी दमदमा रेड लाइट पर तैनात एएसआई जयवीर तथा उनकी टीम ने चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को जांच के लिए रुकवाया। जांच के दौरान जब बाइक का नंबर सिस्टम में डाला गया तो पुलिस भी हैरान रह गई। बाइक पर एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 67 चालान लंबित पाए गए। जांच में सामने आया कि संबंधित मोटरसाइकिल के विरुद्ध अधिकांश चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने, बिना वैध बीमा के वाहन चलाने तथा बिना पीयूसी के वाहन चलाने जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित हैं। यानी चालक लंबे समय से लगातार नियमों की अनदेखी कर रहा था, लेकिन न तो उसने चालान भरे और न ही अपने व्यवहार में सुधार किया। मौके पर वाहन मालिक द्वारा मोटरसाइकिल से संबंधित कोई भी कागजात पेश नहीं किए गए।

बिना लाइसेंस नर्सरी संचालित करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

गुरुग्राम,। फलदार पौधों, सजावटी पौधों एवं अन्य बागवानी फसलों की पौध तैयार करने और नर्सरी संचालित करने वाले सभी संचालकों के लिए हरियाणा में लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा बागवानी पौधशाला अधिनियम 2025 एवं हरियाणा बागवानी पौधशाला नियम 2026 के तहत जिले में अगर कोई नर्सरी संचालक लाइसेंस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला बागवानी अधिकारी नेहा यादव ने बताया कि जिले के सभी नर्सरी संचालक निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी नर्सरी का लाइसेंस बनवाने के लिए जिला बागवानी अधिकारी, गुरुग्राम के कार्यालय में अतिशीघ्र आवेदन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बिना नर्सरी लाइसेंस के नर्सरी संचालित करते हुए पाए जाने वाले संचालकों के खिलाफ प्रशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी, गुरुग्राम के दूरभाष नंबर 0124-2324067 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नर्सरी संचालक अपने संबंधित ब्लॉक के बागवानी विकास अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर संपर्क के लिए गुरुग्राम के बागवानी विकास अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत (मोबाइल नंबर 9695316165), पटौदी के डॉ. रविंद्र सहरावत (9812344454), सोहना के ओंकार राणे (8208541881) तथा फर्रुखनगर की रूपांशी (9306813354) से संपर्क किया जा सकता है।

गांव-गांव चौपाल लगाएगी कांग्रेस,बैठक में बनाई रणनीति

नूंह। जिला कांग्रेस कार्यालय नूंह में जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चौधरी शहीदा खान ने की, जबकि नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में संगठन की पिछले एक महीने की गतिविधियों की समीक्षा करने के साथ आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की गई। बैठक के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से किए गए संगठनात्मक कार्यों और गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही आगामी चौपाल कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना बनाई गई। कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने और आमजन के बीच पार्टी की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस का 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान जिले में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर कथित वोट चोरी के मुद्दे को उठाएंगे। साथ ही लोकतंत्र, चुनावी पारदर्शिता और आमजन के मताधिकार की रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। जिलाध्यक्ष चौधरी शहीदा खान ने कहा कि संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के अधिकारों की रक्षा कांग्रेस की प्राथमिकता है।

पटौदी जटौली अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद अस्थायी बंद

गुरुग्राम। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाजरे की सरकारी खरीद फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। बाजरे की खरीद के लिए संचालित ई-खरीद पोर्टल को भी आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसके चलते फिलहाल बाजरे के गेटपास जारी नहीं हो सकेंगे। मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएम) पंचकूला द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी पत्र के माध्यम से राज्य की मंडियों में बाजरे की खरीद बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पटौदी जटौली अनाज मंडी में भी बाजरे की खरीद प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी। मार्केट कमेटी पटौदी के चेयरमैन मनोज मोकलवास ने बताया कि यदि कोई वास्तविक किसान किसी कारणवश अपनी बाजरा फसल बेचने से वंचित रह गया है, तो ऐसे मामलों का सत्यापन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के उपरांत अनुमोदित किसानों की सूची हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भेजी जाएगी, ताकि पात्र किसानों को ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से बाजरा बेचने की अनुमति मिल सके।

32 लाइसेंसी हथियारों की चोरी पर मानवाधिकार आयोग सख्त

फरीदाबाद,एजेंसी। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने फरीदाबाद के सेक्टर-8 पुलिस थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी पुलिस थानों में मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने अपने आदेश में पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को निर्देशित किया है कि वे इस घटना के दृष्टिगत राज्यभर के पुलिस थानों में हथियारों की सुरक्षित अभिरक्षा, मालखानों तक पहुंच और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा करें।

यह मामला अधिवक्ता गीतांजलि, निवासी पंचकूला द्वारा 16 जुलाई 2026 को आयोग के समक्ष दायर शिकायत के माध्यम से उठाया गया था। शिकायत में कहा गया था कि 32 लाइसेंसी हथियारों के मालिकों ने कानून का पालन करते हुए अपने हथियार पुलिस थाने में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा कराए थे, लेकिन पुलिस मालखाने से इन हथियारों की चोरी होना पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक को दर्शाता है। शिकायतकर्ता ने इस घटना के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा था कि चोरी हुए हथियारों का यदि आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, तो उनके वास्तविक मालिकों को भय, मानसिक तनाव और अनावश्यक कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि उन्होंने स्वयं कानून का पालन किया था। शिकायत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 तथा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 3 के तहत जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के अधिकार का भी उल्लेख किया गया था।

इसके अतिरिक्त, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा और पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद से रिपोर्ट मंगवाने तथा घटना के लिए जिम्मेदार लापरवाही की जांच करने का अनुरोध किया गया था। दीप भाटिया के समक्ष पुलिस उपायुक्त, फरीदाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, मोनू पुत्र राज कुमार पुलिस थाना सेक्टर-8, फरीदाबाद में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। वह थाने की दैनिक डायरी के रखरखाव में सहायता करने के साथ-साथ पुलिस मालखाने से संबंधित कार्य भी करता था। इस दौरान उसे मालखाने में रखे अभिलेखों एवं सामान की जानकारी हो गई थी। जांच के दौरान ईएसआई बिजेंद्र द्वारा हथियारों की चोरी में मोनू की संलिप्तता को लेकर संदेह व्यक्त किया गया। इसके बाद जांच एवं एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर मोनू सहित कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुलिस थाने से गायब हुए सभी हथियार आरोपियों से बरामद कर लिए गए हैं तथा मामले का चालान 6 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला आम नागरिकों के लाइसेंसी हथियारों की सुरक्षा एवं सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में गंभीर चिंता उत्पन्न करता है।

फेसबुक फ्रेंड ने ईंट से कुचलकर की हत्या, पति से छुपक प्रेमी से मिलने आई थी महिला

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की नाईपुरा कॉलोनी में फेसबुक दोस्त से सोमवार की रात को मिलने आई 28 वर्षीय महिला की ईंट से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। महिला अपनी बहन के साथ दोस्त के कमरे पर पहुंची थी। वारदात के बाद आरोपी बैग लेकर भागने लगा, तभी उसकी बहन को शक हुआ। कमरे में महिला का खून से लथपथ शव देखकर वह चीख पड़ी। शोर सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने भाग रहे आरोपी और उसके दोस्त को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि मृतका की पहचान पिंकी पत्नी प्रमोद निवासी गांव मलकपुर, थाना अनूपशहर, जिला बुलंदशहर के रूप में हुई है। आरोपी पिंटू (33) भी बुलंदशहर के गांव शेखपुर गढ़वा थाना खानपुर का रहने वाला है। उनके मुताबिक, पिंकी और पिंटू की दोस्ती करीब चार-पांच महीने पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों फोन पर बातचीत करने लगे थे। 9 नवंबर को पिंकी पिंटू से मिलने नाईपुरा कॉलोनी स्थित उसके कमरे पर पहुंची थी। उनके अनुसार, कमरे में किसी बात को लेकर पिंकी और पिंटू के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी दौरान पिंटू ने पास में पड़ी ईंट से पिंकी के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। उसी मकान में किराए पर रहने वाले प्रतीक ने बताया कि पिंटू अपने दोस्त आर्यन गुप्ता उर्फ बंटी (22) के साथ पांच दिन पहले ही वहां कमरा किराए पर लेकर रहने आया था।

नशा तस्करों पर फरीदाबाद पुलिस की कार्रवाई, 395 मुकदमे दर्ज कर 538 आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद। शहर को नशामुक्त बनाने और नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 395 एनडीपीएस मुकदमे दर्ज किए और 538 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 134 नशा सप्लायर शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय तस्करों और उनकी सप्लाई चेन पर शिकंजा कसने का प्रयास किया गया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, कार्रवाई के दौरान कमर्शियल श्रेणी के 19 एनडीपीएस मुकदमे दर्ज कर 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 25 नशा सप्लायर शामिल हैं। इन मामलों में पुलिस ने 151.655 किलोग्राम गांजा, 272 ग्राम स्मैक, 1.076 किलोग्राम चरस और 2.337 किलोग्राम कोकीन बरामद की है। इसके अलावा 137.97 ग्राम एमडीएमए, 386 ट्रामाडोल इंजेक्शन, 1,080 स्पास्कोरेवॉन प्लस कैप्सूल, 840 ट्रामाडोल कैप्सूल और 9,976 अल्प्राजोलम टैबलेट भी बरामद की गई हैं। वहीं, नॉन-कमर्शियल श्रेणी के 376 एनडीपीएस मुकदमे दर्ज कर 486 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 109 नशा सप्लायर शामिल हैं। इन मामलों में पुलिस ने 224.744 किलोग्राम गांजा, 350.76 ग्राम स्मैक, 405.217 ग्राम चरस, 12.17 ग्राम कोकीन और 3.807 किलोग्राम अफीम बरामद की है। इसके अतिरिक्त ब्यूप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन, पेंटाजोसिन, ट्रामाडोल एवं प्रेगाबालिन कैप्सूल, 17.86 ग्राम एमडीएमए, 1,230 अल्प्राजोलम टैबलेट और 8 ब्यूप्रेनॉर्फिन टैबलेट भी बरामद की गई हैं। फरीदाबाद पुलिस की इस कार्रवाई में कुल 376.399 किलोग्राम गांजा, 622.76 ग्राम स्मैक, 2.337 किलोग्राम कोकीन और 1.481 किलोग्राम चरस सहित विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ एवं प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई हैं। पुलिस का विशेष जोर नशे की सप्लाई करने वाले नेटवर्क और इसके पीछे सक्रिय लोगों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाने पर है। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे की सप्लाई चेन को तोड़ना और इस अवैध कारोबार को बढ़ावा देने वाले लोगों पर शिकंजा कसना भी अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। पुलिस द्वारा छोटे-बड़े तस्करों के साथ-साथ नशे के स्रोतों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।

एक्सपोर्ट गारमेंट कंपनी में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड ने फंसे हुए दो लोगों को सकुशल बाहर निकाला

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोयडा में सोमवार की मध्य रात्रि को थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में स्थित एक एक्सपोर्ट गारमेंट की कंपनी में भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की आठ गाड़ियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में कुछ लोग फंस गए थे, जिन्हें शकुशल बाहर निकाला गया। मुख्य दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सोमवार की मध्य रात्रि को फायर ब्रिगेड को सूचना मिली कि ए-4 सेक्टर 63 स्थित एक गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में आग लग गई है, और कुछ लोग उसमे फंस गए हैं।



उन्होंने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आठ गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि करीब एक घंटे की मस्कट के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया है। आग कंपनी के प्रथम और द्वितीय तल पर लगी थी। शुरुआती दौर में दो लोगों की फंसने की सूचना प्राप्त हुई थी। उन्होंने बताया कि 41 वर्षीय विक्की और 26 वर्षीय अरुण प्रथम तल पर कंपनी के अंदर सो रहे थे। वह आग में फंस गए थे। रेस्क्यू करके उन्हें बाहर निकाला गया तथा उनकी जान बचाई गई। उन्होंने बताया कि दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर जगह-जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की गई थी। जिसका फायदा मिला और तुरंत गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि कूल डाउन प्रक्रिया जारी है। आग लगने के कारण और आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

गुरुग्रामः बिजवासन टोल पर परिवार से मारपीट में टोल कंपनी पर एनएचएआई ने ठोंका 15 लाख जुर्माना

गुरुग्राम,एजेंसी। द्वारका एक्सप्रेसवे के बिजवासन टोल प्लाजा पर कार सवार परिवार के साथ विवाद में परिवार के सदस्यों को बूम बैरियर से पीटने का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कड़ा संज्ञान लिया है। एनएचएआई की ओर से टोल संचालन करने वाली कांट्रेक्ट कंपनी मेसर्स रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही कंपनी को शो कॉज नोटिस देकर पूछा है कि क्यों न आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। किसी भी टोल पर मारपीट की घटना में यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।



जानकारी के अनुसार द्वारका एक्सप्रेसवे पर बिजवासन टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर हुए विवाद में टोल कर्मियों ने कार सवार परिवार के साथ मारपीट की थी। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि विवाद के दौरान कर्मचारियों ने बूम बैरियर तक उठाकर परिवार पर हमला कर दिया था। वीडियो वायरल होने पर लोगों में टोल कर्मियों के व्यवहार को लेकर भारी आक्रोश फैल गया था। वीडियो वायरल होने के बाद एनएचएआई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए थे। जांच में टोल कंपनी की लापरवाही और कर्मचारियों का हिंसक व्यवहार सामने आया। एनएचएआई ने कहा कि टोल प्लाजा पर यात्रियों के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टोल कर्मियों का काम यातायात को सुचारू करना है, न कि लोगों के साथ मारपीट करना। एनएचएआई ने कंपनी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में कंपनी से जवाब मांगा गया है कि आखिर क्यों न उसके खिलाफ ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की जाए। अगर कंपनी का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उसे भविष्य में किसी भी टोल के संचालन से वंचित किया जा सकता है। इसके साथ ही एनएचएआई ने टोल प्लाजा पर तैनात संबंधित कर्मचारियों को तुरंत हटाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कंपनी को अपने सभी कर्मचारियों को व्यवहार और प्रशिक्षण के बारे में सख्त निर्देश देने को कहा गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। इस मामले में पुलिस भी जांच कर रही है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर टोल कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। लोगों ने एनएचएआई की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई हर घटना में होनी चाहिए, ताकि टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी खत्म हो सके।

80 प्रतिशत पैसे लेकर भी किया फ्लैट का आवंटन रद्द, मामला दर्ज

फरीदाबाद। फरीदाबाद सेक्टर-45 स्थित सरवोम प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कंपनी ने तीन फ्लैट की कुल कीमत का 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान लेने के बावजूद खरीदारों का आवंटन रद्द कर दिया और वर्ष 2024 में वही फ्लैट दूसरे लोगों को बेच दिए।

इस मामले में पुलिस ने कंपनी जॉतिंद्रा स्टील (इंफ्रास्ट्रक्चर) लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता राजीव नाथवानी, हरि राम और गौरव नाथवानी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें सेक्टर-45 स्थित सरवोम प्रोजेक्ट में दो कमरे वाले फ्लैट आवंटित किए गए थे। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2023-24 में फ्लैट की कुल कीमत का 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान कर दिया था।

आरोप है कि कंपनी ने वर्ष 2024 में उनके फ्लैटों का आवंटन रद्द कर दिया और उन्हें दूसरे खरीदारों को बेच दिया।

गुरुग्राम में अब हर 60 दिन में होगा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का तबादला

गुरुग्राम। भ्रष्टाचार के विरुद्ध गुरुग्राम पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए बड़े और सख्त कदम उठाए हैं। ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान किसी भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी, होमगार्ड या एसपीओ की संलिप्तता पाए जाने पर अब जोनल ऑफिसर (जेडओ) और ट्रैफिक इंस्पेक्टर (टीआई) की भी जिम्मेदारी तय होगी। साथ ही बॉडी वार्न कैमरा के बिना वाहन रुकवाने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इस तरह के आदेश पुलिस आयुक्त शिवास कविराज की ओर से दिए गए हैं।

पुलिस आयुक्त शिबास कबिराज ने भ्रष्टाचार, लापरवाही, अवैध वसूली, अनुचित व्यवहार सहित किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अधिकारियों को आदेश देते हुए पुलिस आयुक्त शिवास कविराज ने कहा कि एसीपी स्तर के अधिकारी सीसीटीवी कंट्रोल रूम के माध्यम से भ्रष्टाचार निरोधी निगरानी करेंगे। साथ ही प्रत्येक 60 दिन के बाद स्वचालित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का तबादला होगा। सोशल मीडिया पर होमगार्ड द्वारा उपहार के नाम पर अवैध वसूली करने के संबंध में वायरल हुई वीडियो के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार करने के साथ ही गुरुग्राम पुलिस के सभी डीसीपी, एसीपी के माध्यम से ग्राउंड लेवल के पुलिसकर्मियों को सख्त आदेश दिए हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित क्षेत्र के जेडओ एवं टीआई की जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम में एसीपी रैंक के अधिकारी सभी सीसीटीवी कैमरों की नियमित रूप से जांच एवं निगरानी सुनिश्चित करेंगे, ताकि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नजर रखी जा सके। यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्यवाही बॉडी वार्न कैमरे की निगरानी में करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे तथा वाहन चालकों एवं पुलिसकर्मियों दोनों के हित सुरक्षित रहें।

गुरुग्रामः प्रदूषण फैलाने वालों पर 17 दिन में लगाया 45.82 लाख रुपये जुर्माना

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की प्रवर्तन टीमें प्रदूषण और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी कड़ी में 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 2026 तक 17 दिन में विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों पर कुल 634 चालान जारी किए गए। चालान काटकर 45,82,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई शहर में स्वच्छता नियमों का पालन सुनिश्चित कराने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई। नगर निगम की प्रवर्तन टीमों ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग के मामलों में 177 चालान जारी किए।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के 88 और डस्ट मिटिगेशन नियमों की अवहेलना के 85 मामलों में कार्रवाई की गई। इसके अलावा कूड़ेदान उपलब्ध नहीं होने पर 80 चालान किए गए। खुले में कचरा जलाने के 54 मामलों में कार्रवाई की गई, जबकि पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ भी 54 चालान जारी किए गए। निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) वेस्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर 22 तथा निर्माण कार्य बंद करने के आदेशों की अवहेलना करने पर 11 चालान किए गए। निगम की कार्रवाई में बिना ढके निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहन, अवैध रूप से कचरा डालने, स्टॉर्म वाटर ड्रेन में अवैध कनेक्शन, खुले में शौच, सेप्टेज संबंधी उल्लंघन और अन्य स्वच्छता नियमों के मामले भी शामिल रहे। एमसीजी की ओर से दावा किया गया है कि सडक़ों को धूल मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नियमित रोड स्वीपिंग, प्रमुख सडक़ों पर पानी का छिडक़ाव, सडक़ किनारों पर जमा मिट्टी को हटाने और धूल नियंत्रण के अन्य उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एंटी-स्मॉग गन भी तैनात की गई हैं। इनके माध्यम से धूल कणों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निगम की टीमें सडक़ों और आसपास के क्षेत्रों की नियमित सफाई कर रही हैं, ताकि धूल के स्रोतों को कम किया जा सके और नागरिकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

सात माह बाद भी ड्राइवर कल्याण बोर्ड नहीं हुआ लागू : योगेश शर्मा

गुरुग्राम। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक एवं महान राष्ट्रवादी श्रमिक चिंतक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जयंती पर बुधवार को हरियाणा ऑटो चालक संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। यहां देवीलाल कॉलोनी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कुलदीप यादव ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ।

बैठक में बतौर मुख्य वक्ता भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष योगेश शर्मा उपस्थित रहे। बैठक का संचालन अनिल कुमार ने किया। अपने संबोधन में योगेश शर्मा ने कहा कि परम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कर देश के श्रमिक आंदोलन को एक नई वैचारिक दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि सात माह बीतने के बाद भी हरियाणा सरकार ने ड्राइवरों के लिए कल्याण बोर्ड को लागू नहीं किया। ऑटो चालकों के लिए स्थाई स्टैंड पिछले सात साल से नहीं बने। उन्होंने कहा कि सरकार घोषणाएं तो करती है, लेकिन जमीन पर उन्हें लागू नहीं करती। इससे ड्राइवरों में भारी रोष है। योगेश



शर्मा ने आगामी 19 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले एक दिवसीय राष्ट्रीय महाधरने में हरियाणा से अधिक से अधिक संख्या में ड्राइवरों एवं कार्यकर्ताओं को भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय महाधरने में देश के लगभग 22 प्रदेशों से भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि भाग लेंगे तथा केंद्र सरकार को ड्राइवरों की समस्याओं और अधिकारों से संबंधित 11 सूत्रीय मांगपत्र सौंपेंगे।

कैंसर के महंगे इलाज पर मोदी सरकार का निर्णायक वार

डॉ. मयंक चतुर्वेदी



जिस कैंसर के इलाज में महंगी दवाओं का खर्च अक्सर परिवारों की जीवनभर की जमा पूंजी तक खत्म कर देता है, उसी दवा बाजार के मुनाफे पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। वस्तुत: स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का यह हस्तक्षेप बताता है कि गंभीर बीमारियों के उपचार को आर्थिक रूप से सुलभ बनाने के लिए दवा बाजार के व्यापारिक मुनाफे पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है जितना चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार। एक तरह से देखा जाए तो देश में आधुनिक कैंसर उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं इतनी महंगी हैं कि सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए उनका नियमित इस्तेमाल कठिन हो जाता है। ऐसे में मोदी सरकार ने दवा की कीमतों में कमी लाने के लिए सीधे उस व्यवस्था पर हस्तक्षेप किया है, जहां निर्माता से लेकर वितरक और खुदरा विक्रेता तक जुड़ने वाला व्यापारिक लाभ अंतिम कीमत को प्रभावित करता है। केंद्र सरकार ने 1,364 एंटी-कैंसर दवा फॉर्मूलेशन की कीमतों में भारी कटौती करते हुए कुछ दवाओं के दाम 96.45 प्रतिशत तक घटा दिए हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। वस्तुत: ट्रेड मार्जिन का आशय निर्माता से दवा वितरक तक पहुंचने वाली कीमत और मरीज को बेची जाने वाली खुदरा कीमत के बीच के अंतर से है। इस अंतर में वितरण और खुदरा कारोबार से जुड़े व्यापारिक लाभ शामिल होते हैं। कई दवाओं के मामले में यही अंतर अंतिम कीमत को काफी महंगा बना देता है। नई व्यवस्था के तहत इन दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य मार्च 2026 के औसत वितरक मूल्य को आधार बनाकर निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता लाना और मरीजों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना है।

अब एनपीपीए के आंकड़े इस फैसले के व्यापक प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं से संबंधित 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतों की जानकारी दी है। इनमें 679 ब्रांड ऐसे हैं, जिनकी कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है। सबसे बड़ी कटौती 96.45 प्रतिशत दर्ज की गई है। बेवेसिजुमैब 100 एमजी इंजेक्शन के ब्रांड ब्रिक्स्टा की कीमत 25,995 रुपये से घटाकर 3,318 रुपये कर दी गई है। इसी औषधीय घटक वाले रिलायंस लाइफ साइंसेज के बेवासीरेल की कीमत 24,079 रुपये से घटकर 3,985 रुपये रह गई है। प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एबिराटेरोन एसीटेट 250 एमजी टैबलेट के ब्रांड एबिरोन की कीमत 41,250 रुपये से घटाकर 3,218.23 रुपये कर दी गई है। स्तन कैंसर के उपचार में उपयोगी फुलवेस्ट्रेंट इंजेक्शन के ब्रांड फासनॉर्म का अधिकतम खुदरा मूल्य 30,421.87 रुपये से घटकर 3,671.73 रुपये हो गया है। इसी प्रकार रक्त कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एजासिटिडीन इंजेक्शन की कीमत 7,790 रुपये से घटाकर 1,397 रुपये कर दी गई है। इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसके दायरे में आधुनिक कैंसर उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई महंगी दवाएं शामिल हैं। इनमें पेम्ब्रोलिजुमैब, डुरवालुमैब और ओसिमर्टिनिब जैसी दवाएं प्रमुख हैं। इनका उपयोग रोग की प्रकृति और मरीज की चिकित्सकीय स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में किया जाता है।

इसके अतिरिक्त बेवेसिजुमैब, डेनोसुमैब और पेगफिलग्रास्टिम जैसी दवाओं को भी मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया गया है। बेवेसिजुमैब का इस्तेमाल कोलोन, ओवरी और सर्वाइकल कैंसर सहित विभिन्न कैंसर के उपचार में किया जाता है। डेनोसुमैब का उपयोग हड्डियों से जुड़ी जटिलताओं के प्रबंधन में और पेगफिलग्रास्टिम का इस्तेमाल कीमोथेरेपी के दौरान श्वेत रक्त कोशिकाओं में कमी से बचाव के लिए किया जाता है। सूची में पेटेंट वाली दवाओं को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। इससे आधुनिक उपचार पद्धतियों में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं के खुदरा मूल्य पर नियंत्रण का दायरा विस्तृत हुआ है। वैसे कैंसर की दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर नियंत्रण की शुरुआत मोदी सरकार के रहते हुए वर्ष 2019 में हुई थी। उस समय एनपीपीए ने 42 गैर-अनुसूचित एंटी-कैंसर दवाओं के व्यापारिक मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित किया था। इसके बाद 526 ब्रांडों की कीमतों में कमी दर्ज की गई थी। अब वर्ष 2026 में सरकार ने इस व्यवस्था का विस्तार करते हुए 137 दवाओं को इसके दायरे में शामिल किया है। वस्तुत: यह कदम भारत की व्यापक औषधि मूल्य नियंत्रण नीति से भी जुड़ा है। ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ), 2013 के तहत आवश्यक औषधियों की अधिकतम कीमत निर्धारित करने और अन्य दवाओं के मूल्य की निगरानी का प्रावधान है। राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची 2022 में 388 औषधियां शामिल हैं, जिनमें 63 कैंसर-रोधी दवाएं हैं। इन अनुसूचित दवाओं की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नई ट्रेड मार्जिन व्यवस्था गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर भी मूल्य नियंत्रण का प्रभाव बढ़ाती है। इसके साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं कम कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास भी जारी है। इन पहलों का साझा उद्देश्य दवाओं की कीमतों में अंतर कम करना और आम नागरिकों के लिए उपचार की आर्थिक पहुंच बढ़ाना है। दवाओं की कीमतों में कटौती के साथ उनकी उपलब्धता और सरकारी आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन भी महत्वपूर्ण है। संशोधित कीमतें लागू होने के बाद दवा कंपनियों को नई मूल्य सूची वितरकों, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों की फार्मेसी को भी संशोधित एमआरपी प्रदर्शित करनी होगी। राज्य औषधि नियंत्रकों को आदेश के अनुपालन की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। दवा कंपनियों से उत्पादन और आपूर्ति का मौजूदा स्तर बनाए रखने को भी कहा गया है, ताकि मूल्य कटौती के बाद बाजार में दवाओं की उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका पैदा न हो। मरीज दवा के पैक पर छपी संशोधित एमआरपी देख सकते हैं। 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप और एनपीपीए की वेबसाइट ठ्ठश्चश्चड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ पर भी कीमतों की पुष्टि की जा सकती है। किसी मेडिकल स्टोर या अस्पताल की फार्मेसी द्वारा निर्धारित एमआरपी से अधिक राशि वसूलने पर 'फार्मा जन समाधान' पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए एनपीपीए की हेल्पलाइन 1800-111-255 भी उपलब्ध है। वस्तुत: इस मामले में कहना यही होगा कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मरीज और उसका परिवार पहले ही शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कठिन दौर से गुजरता है। ऐसे समय में हजारों और कई मामलों में लाखों रुपये की दवाओं का खर्च कम होना किसी परिवार के लिए बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह फैसला स्वास्थ्य नीति को आम आदमी की आर्थिक जरूरतों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। दवा कंपनियों के व्यापारिक मार्जिन पर सीमा तय करके सरकार ने स्पष्ट किया है कि जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों के निर्धारण में मरीजों के हित और उनकी आर्थिक क्षमता को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। सो, सरकार उस प्राथमिकता को केंद्र में रखकर स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रही है।

भाई दूज के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की संतानों यमराज तथा यमुना से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, यमुना अपने भाई यमराज से अत्यंत स्नेह करती थीं और उन्हें बार-बार अपने घर आने का निमंत्रण देती थी। अंततः कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन के घर पहुंचे। यमुना ने उनका आत्मीय स्वागत किया, मस्तक पर तिलक लगाया, आरती उतारी और स्वादिष्ट भोजन कराकर सत्कार किया। बहन के प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। यमुना ने प्रार्थना की कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाए और उसका आतिथ्य स्वीकार करे, उसे अकाल मृत्यु का भय न सताए। यमराज ने यह वरदान प्रदान किया। तभी से यह पर्व यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य धार्मिक मान्यता भगवान श्रीकृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी है। कहा जाता है कि नरकासुर का वध करने के बाद श्रीकृष्ण जब सुभद्रा के पास पहुंचे तो उन्होंने दीप प्रज्वलित कर तिलक लगाकर और आरती उतारकर उनका स्वागत किया तथा उनकी मंगलकामना की। इस प्रसंग को भी भाई दूज की तिलक परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन यमुना स्नान का भी विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना नदी में स्नान करने और यमराज की पूजा-अर्चना करने से मनुष्य को यम के भय से मुक्ति तथा पुण्यफल की प्राप्ति होती है।

एक तिलक, हजारों भावनाएं और भाई दूज का अनमोल रिश्ता

अतुल गोयल



भारतीय संस्कृति में पर्व और त्योहार मानवीय रिश्तों की गरिमा, पारिवारिक एकता, सामाजिक सद्भाव और जीवन-मूल्यों को सहेजने के सशक्त माध्यम हैं। इन्हीं विशिष्ट पर्वों में भाई दूज का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीपावली के उल्लासमय पांच दिवसीय उत्सव का समापन करने वाला यह पर्व भाई-बहन के निश्छल प्रेम, अटूट विश्वास, आत्मीयता और परस्पर जिम्मेदारी का अनुपम प्रतीक है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया और भाई टीका जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस वर्ष भाई दूज 11 नवंबर को मनाई जाएगी। इस वर्ष भाई दूज की तिथि को लेकर कुछ भ्रम इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि दो कैलेंडर तिथियों में व्याप्त है। पंचांग के अनुसार द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे प्रारंभ होकर 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि और अपराह्न काल में द्वितीया की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर को भाई दूज मनाना उचित माना गया है। यह पर्व भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में भाई-बहन के रिश्ते की विशिष्टता को रेखांकित करता है। रक्षाबंधन में जहां बहन भाई की कलाई पर रक्षा-सूत्र बांधकर उसकी मंगलकामना करती है, वहीं भाई दूज पर वह अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उसके स्वस्थ, दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना करती है। भाई भी बहन को उपहार देकर उसके प्रति अपने स्नेह, सम्मान और सहयोग का भाव प्रकट करता है। यह रिश्ता किसी औपचारिक वचन अथवा सामाजिक बंधन से नहीं बल्कि बचपन की साझा स्मृतियों, निश्छल भावनाओं, परस्पर विश्वास और जीवनभर एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बने रहने की भावना से निर्मित होता है। यही कारण है कि भाई दूज का उत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में रिश्तों की भावनात्मक गहराई का जीवंत उत्सव है।

भाई दूज के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की संतानों यमराज तथा यमुना से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, यमुना अपने भाई यमराज से अत्यंत स्नेह करती थीं और उन्हें बार-बार अपने घर आने का निमंत्रण देती थी। अंतत: कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन के घर पहुंचे। यमुना ने उनका आत्मीय स्वागत किया, मस्तक पर तिलक लगाया, आरती उतारी और स्वादिष्ट भोजन कराकर सत्कार किया। बहन के प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। यमुना ने प्रार्थना की कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाए और उसका आतिथ्य स्वीकार करे, उसे अकाल मृत्यु का भय न सताए। यमराज ने यह वरदान प्रदान किया। तभी से यह पर्व यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य धार्मिक मान्यता भगवान श्रीकृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी है। कहा जाता है कि नरकासुर का वध करने के बाद श्रीकृष्ण जब सुभद्रा के पास पहुंचे तो उन्होंने दीप प्रज्वलित कर तिलक लगाकर और आरती उतारकर उनका स्वागत किया तथा उनकी मंगलकामना की। इस प्रसंग को भी भाई दूज की तिलक परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन यमुना स्नान का भी विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना नदी में स्नान करने और यमराज की पूजा-अर्चना करने से मनुष्य को यम के भय से मुक्ति तथा पुण्यफल की प्राप्ति होती है। इस परंपरा में यमुना केवल एक पवित्र नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी शक्ति, पवित्रता, करुणा और भाई-बहन के दिव्य स्नेह की प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हैं।

भाई दूज का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पक्ष यमराज की पूजा के साथ-साथ चित्रगुप्त आराधना से भी जुड़ा है। यमराज को मृत्यु और न्याय का देवता माना जाता है जबकि भगवान चित्रगुप्त को मनुष्य के कर्मों का लेखा-जोखा रखने वाला देवता बताया गया है। विशेष रूप से कायस्थ समाज में कार्तिक शुक्ल द्वितीया को चित्रगुप्त पूजा और लेखनी-दवात पूजन की परंपरा है। इस अवसर पर नई बही-खातों और लेखन सामग्री की पूजा की जाती है। इसका आध्यात्मिक संदेश अत्यंत गहरा है कि मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए क्योंकि उसके कर्म ही उसके जीवन की दिशा और भविष्य का निर्धारण करते हैं। भाई दूज की परंपराएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों और सांस्कृतिक स्वरूपों में दिखाई देती हैं। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में इसे 'भाऊ बीज' कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में यह 'भाई फोंटा' के नाम से प्रसिद्ध है, जहां बहनें विशेष विधि से चंदन, दही और काजल आदि से भाई के मस्तक पर फोंटा लगाती हैं। नेपाल में यह पर्व 'भाई टीका' के रूप में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। वहां बहनें भाइयों के माथे पर सप्तरंगी टीका लगाती हैं और उनके दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। इन सभी परंपराओं में धार्मिक विधियों की भिन्नता के बावजूद भाई-बहन के प्रेम और मंगलकामना का मूल भाव समान है। यह विविधता भारतीय संस्कृति की उस विशेषता को दर्शाती है, जिसमें अलग-अलग भाषाओं, रीति-रिवाजों और क्षेत्रीय परंपराओं के बावजूद पारिवारिक मूल्यों की एकता बनी रहती है। भाई दूज का महत्व इस दृष्टि से भी विशेष है कि यह पर्व रिश्तों में निहित अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य का भी स्मरण कराता है। भारतीय परंपरा में भाई को बहन का संरक्षक माना गया है लेकिन इस रिश्ते की वास्तविक सुंदरता एक-दूसरे की रक्षा करने की पारस्परिक भावना में निहित है। बदलते सामाजिक परिवेश में जब एकल परिवारों, व्यस्त जीवनशैली, भौगोलिक दूरियों और डिजिटल संचार के कारण पारिवारिक मेल-मिलाप के अवसर सीमित होते जा रहे हैं, तब भाई दूज जैसे त्योहार रिश्तों को पुनर्जीवित करने और भावनात्मक निकटता बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। यह पर्व बताता है कि भाई-बहन का संबंध केवल बचपन की यादों तक सीमित नहीं होता बल्कि उम्र के हर पड़ाव पर एक-दूसरे का संबल बनने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भाई दूज का संदेश और भी व्यापक है। यमराज और यमुना की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, करुणा, आत्मीयता और पारिवारिक संबंधों का महत्व जीवन की तमाम व्यस्तताओं से कहीं अधिक है। यमुना द्वारा अपने भाई के लिए की गई मंगलकामना निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है जबकि यमराज द्वारा बहन की इच्छा स्वीकार करना पारिवारिक भावनाओं के सम्मान का संदेश देता है। यह पर्व हमें अपने रिश्तों को केवल औपचारिकताओं में नहीं बल्कि संवेदना, विश्वास, त्याग और सहयोग के माध्यम से जीवंत बनाए रखने की प्रेरणा देता है।

वास्तव में, भाई दूज का तिलक केवल बहन के हाथों से भाई के मस्तक पर लगाया जाने वाला रोली और अक्षत नहीं है बल्कि उसमें छिपी होती है बहन की प्रार्थना, भाई का विश्वास और जीवनभर एक-दूसरे के साथ खड़े रहने की भावना। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि धन-दौलत और भौतिक सुख-सुविधाओं से कहीं अधिक मूल्यवान वे रिश्ते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में हमारा संबल बनते हैं। दीपावली के दीपों की जगमगाहट के बीच मनाया जाने वाला भाई दूज इसी स्नेह और विश्वास का प्रकाश फैलाता है। इसकी वास्तविक सार्थकता तभी है, जब भाई-बहन तिलक और उपहारों की रस्म से आगे बढ़कर एक-दूसरे के सम्मान, स्वतंत्रता, खुशियों और कठिनाइयों का भी ध्यान रखें। यही भाई दूज का शाश्वत आध्यात्मिक संदेश और भारतीय पारिवारिक संस्कृति की सबसे सुंदर पहचान है।

विचार

प्रतिबंध नहीं, सुरक्षित डिजिटल संसार की जरूरत

डॉ. प्रियंका सौरभ

इक्कीसवीं सदी में इंटरनेट केवल मनोरंजन या संवाद का माध्यम नहीं रह गया है बल्कि शिक्षा, सूचना, अभिव्यक्ति और सामाजिक सहभागिता का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। विशेषकर बच्चों के लिए डिजिटल दुनिया ज्ञान के नए द्वार खोलती है। ऐसे समय में बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह वंचित करना उनके विकास के अवसरों को सीमित करने जैसा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों की इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार से जुड़े अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के नाम पर व्यापक और एकमुश्त प्रतिबंध उचित समाधान नहीं हो सकते। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ड्ड) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापक व्याख्या में डिजिटल पहुँच का महत्व भी सामने आता है। हालांकि, इस अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के इंटरनेट की खुली छूट दे दी जाए। बच्चों के शैक्षणिक विकास में इंटरनेट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज डिजिटल पुस्तकालय, ऑनलाइन कक्षाएँ, शैक्षणिक वीडियो, आभासी प्रयोगशालाएँ और विभिन्न शिक्षण मंच पारंपरिक शिक्षा के पूरक बन चुके हैं। केंद्र सरकार के दीक्षा (ष्ठड्ढक्रयस्र॥) मंच और पीएम ई-विद्या जैसी पहल ने डिजिटल शिक्षा को व्यापक बनाने में योगदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए इंटरनेट गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री तक पहुँच का माध्यम बन सकता है। जिन विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक, पुस्तकालय या अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ डिजिटल माध्यम शिक्षा की कमियों को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। इंटरनेट बच्चों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखता बल्कि उनकी रचनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन को भी प्रोत्साहित करता है। वे विज्ञान, साहित्य, इतिहास, पर्यावरण, कला और तकनीक जैसे विषयों पर अपनी रुचि के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कविताएँ, कहानियाँ, चित्र और विचार साझा कर सकते हैं। इससे उनमें अभिव्यक्ति का आत्मविश्वास और संवाद की क्षमता विकसित होती है। सूचना का अधिकार भी इंटरनेट के माध्यम से अधिक प्रभावी बनता है। बच्चे अपने आसपास की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को समझकर जागरूक नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। डिजिटल पहुँच समावेशी शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। दिव्यांग बच्चों के लिए स्क्रीन रीडर, ऑडियो पुस्तकें, सांकेतिक भाषा आधारित सामग्री और अन्य सहायक तकनीकें शिक्षा को अधिक सुलभ बनाती हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को भी देश-दुनिया के शैक्षणिक संसाधनों से जुड़ने का अवसर मिलता है। इंटरनेट डिजिटल साक्षरता विकसित करता है, जो भविष्य के रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल बन चुकी है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन शोध, डिजिटल संचार और तकनीकी नवाचार के दौर में बच्चों को डिजिटल दुनिया से दूर रखना उनके भविष्य की संभावनाओं को कमजोर कर सकता है।

हालाँकि, इंटरनेट के लाभों के साथ गंभीर चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा आज अभिभावकों, शिक्षकों, सरकार और डिजिटल मंचों के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन यौन शोषण, बच्चों को बहला-फुसलाकर अनुचित गतिविधियों में शामिल करना, साइबर बुलिंग, अश्लील सामग्री, फर्जी पहचान और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी घटनाएँ बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। कई बार बच्चे अनजान व्यक्तियों से संपर्क में आ जाते हैं और अपनी निजी जानकारी, तस्वीरें या स्थान संबंधी विवरण साझा कर देते हैं। इसका दुरुपयोग उनके मानसिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। साइबर बुलिंग भी एक गंभीर समस्या है। सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियाँ, धमकियाँ, मजाक उड़ाना और निजी तस्वीरों का दुरुपयोग बच्चों के आत्मविश्वास तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल मंचों द्वारा बच्चों के व्यवहार, पसंद और व्यक्तिगत जानकारी का अत्यधिक संग्रह उनकी निजता के अधिकार के लिए चुनौती है। एल्गोरिदम आधारित सामग्री बच्चों को लगातार स्क्रीन पर बनाए रखने का प्रयास करती है, जिससे उनकी पढ़ाई, नींद, शारीरिक गतिविधियों और सामाजिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए समाधान इंटरनेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में नहीं बल्कि सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण तैयार करने में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार आधारित दृष्टिकोण का मूल संदेश भी यही है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले उपाय तर्कसंगत, आनुपातिक और उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए। किसी विशेष खतरे के समाधान के नाम पर सभी बच्चों की इंटरनेट पहुँच समाप्त कर देना उचित नहीं है। प्रतिबंधों के बजाय जोखिम के अनुसार सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए।

एक नजर

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा



पटना,एजेंसी। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को पटना में गंगा किनारे स्थित विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने दीघा के नासरीगंज घाट से गाय घाट और कंगन घाट तक स्टीमर से भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नितिन नवीन ने गंगा तट पर छठव्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने घाटों की साफ-सफाई और समतलीकरण, सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और वॉच टावर, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, पेयजल की उपलब्धता, रोशनी और निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ ही आपातकालीन चिकित्सा एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद नितिन नवीन ने कहा कि छठ महापर्व बिहार की गहरी आस्था, संस्कृति और समृद्ध लोक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। यह पर्व धार्मिक निष्ठा के साथ सामाजिक समरसता, अनुशासन और प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि गंगा तट पर अर्घ्य देने आने वाले प्रत्येक छठव्रती को सुरक्षित, स्वच्छ और सहज वातावरण मिले, इसके लिए बिहार सरकार और आमजन मिलकर प्रयास कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि समय रहते सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए जाएं, जिससे कि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो और वे पूरे उल्लास एवं श्रद्धा के साथ महापर्व मना सकें।

राघोपुर रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण, बनेगा 30 बेड का नया भवन



सुपौल,एजेंसी। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में मंगलवार को बीएमएसआईसीएल के प्रबंध निदेशक सुब्रत कुमार सेन के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने राघोपुर रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। टीम में जिलाधिकारी सावन कुमार, मुख्य महाप्रबंधक शैलेन्द्र भारती और उप महाप्रबंधक धनंजय कुमार भी शामिल रहे। टीम ने इससे पहले दीनापट्टी स्थित मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का जायजा लिया। इस क्रम में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, संसाधनों और अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अस्पताल के पुराने एवं अत्यंत जर्जर भवन की स्थिति को देखते हुए उसे परित्यक्त घोषित कर दिया। इसके स्थान पर 30 बेड की क्षमता वाले नए भवन का अलग से निर्माण कराने की बात कही गई। नए भवन के निर्माण से अस्पताल में मरीजों के लिए बेड की उपलब्धता बढ़ने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की उम्मीद है। अधिकारियों ने अस्पताल के प्रसव कक्ष, प्रसूति ऑपरेशन कक्ष और आपातकालीन विभाग के संचालन पर विशेष ध्यान दिया। इन विभागों में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बीएमएसआईसीएल की ओर से आवश्यक आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दीप नारायण राम और अस्पताल प्रबंधक अविनाश कुमार ने अस्पताल के विभिन्न विभागों के संचालन में आ रही समस्याओं तथा आवश्यक संसाधनों की कमी से अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और मरीजों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। अधिकारियों के निरीक्षण के बाद राघोपुर रेफरल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत संरचना में सुधार की उम्मीद जगी है। 30 बेड के नए भवन के निर्माण और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता से राघोपुर सहित आसपास के क्षेत्र के मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

12.50 ग्राम ब्राउन शुगर और नकदी के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार



भागलपुर। जिले में युवाओं को नशे की लत से बचाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष महाअभियान 'स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर' के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जगदीशपुर थाना पुलिस ने पुरैनी अहमदखानी गांव में छापेमारी कर 12.50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तीन अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी कार्यालय से मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जगदीशपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पुरैनी अहमदखानी निवासी ईलियास शाह अपने घर में अवैध मादक पदार्थ रखकर उसकी खरीद-बिक्री कर रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक (के निर्देश, सिटी एसपी की निगरानी और डीएसपी (विधि-व्यवस्था) और जगदीशपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने जब ईलियास शाह के घर के पास घेराबंदी की, तो पुलिस बल को देखकर कुछ युवक भागने लगे। सशस्त्र बल की मदद से पुलिस ने खदेड़ कर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान पुरैनी अहमदखानी निवासी ईलियास शाह (पिता मनीर शाह), सानू (पिता मो. रशीद) और मो. इब्राहिम (पिता स्व. जसीम) के रूप में हुई है।

नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को बिहार दौरे को लेकर राजग की बैठक

पटना,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को प्रस्तावित बिहार दौरे और वैशाली में आयोजित होने वाले विशाल कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की पटना जिला स्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रभारी हरीश द्विवेदी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सह बिहार के सह-प्रभारी रोहन गुप्ता, जदयू के वरिष्ठ मंत्री एवं विधानसभा में विधायक दल के नेता श्रवण कुमार सहित एनडीए के सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

बैठक में कार्यक्रम को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई। इस दौरान 11, 12 और 13 नवंबर को प्रखंड स्तर पर तथा 17 और 18 नवंबर को विधानसभा स्तर पर बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कहा कि भाजपा कार्यालय में राजग की यह संयुक्त बैठक उन लोगों को स्पष्ट संदेश है, जो गठबंधन को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैलाते हैं। बिहार में राजग पूरी एकजुटता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। सभी घटक दल एक साथ मिलकर सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन बाबू के रूप में पहचान बनाने वाले नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई यात्रा शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के समग्र विकास में केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का संकल्प व्यक्त किया था। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री 21 नवंबर को वैशाली के राजापाकर पहुंच रहे हैं, जहां करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। यह बिहार के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। राजग के सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक स्वागत करें।



हरीश द्विवेदी ने कहा कि किसी नेता का सच्चा स्वागत केवल सभा में भीड़ जुटाने से नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने से होता है। नीतीश कुमार के कार्यकाल की उपलब्धियों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हो रही प्रगति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 12 वर्षों में गरीबों, किसानों और मजदूरों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों की चर्चा प्रत्येक गांव और घर में होनी चाहिए।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपसी संवाद के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजापाकर की रैली में सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ शामिल हों। 21 नवंबर को पूरे बिहार में उत्सव जैसा वातावरण बनना चाहिए। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में विकसित बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि 20 नवंबर को राजग सरकार का एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड स्थित जाफरपट्टी के 1200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले औद्योगिक एस्टेट में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार आगमन का आग्रह स्वीकार कर लिया है। उनका 21 नवंबर को आगमन इस उत्सव को विशेष बनाएगा। राजग के कोर ग्रुप ने तय किया है कि सभी घटक दल मिलकर इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाएंगे।

उन्होंने कहा कि नवंबर 2005 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग सरकार ने बिहार को जंगलराज से निकालकर सुशासन स्थापित किया। आधारभूत संरचना का व्यापक विकास हुआ और कानून का राज कायम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास को नई गति दे रही है। आज एक्सप्रेस कॉरिडोर, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की स्थापना हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सह बिहार के सह-प्रभारी रोहन गुप्ता ने कहा कि एक वर्ष पूर्व चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं ने हर विधानसभा और हर बूथ तक पहुंचकर जनता से समर्थन मांगा था। जनता ने राजग को अपना पूर्ण आशीर्वाद दिया। यह कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, गठबंधन की नीतियों और एकजुटता की जीत है। शिक्षा, सुरक्षा, सड़क और सुशासन के जो वादे किए गए थे, वे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लगातार पूरे किए जा रहे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राजग के कार्यकर्ताओं ने हर परिस्थिति में कार्यक्रमों को सफल बनाया है और कभी पीछे कदम नहीं हटाया। वर्ष 2005 से पहले बिहार जिन गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा था, उससे नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य को बाहर निकालकर विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि प्रधानमंत्री के विशाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटें, ताकि प्रधानमंत्री प्रसन्न होकर बिहार के लिए और बड़ी योजनाओं की घोषणा करें। उन्हें विश्वास है कि प्रखंड स्तर तक बैठकें आयोजित कर कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। 'हम' के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार ने कहा कि राजग की ताकत उसकी एकजुटता और साझा विकास संकल्प में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। वैशाली में आयोजित होने वाला कार्यक्रम बिहार के विकास और औद्योगिक संभावनाओं को नई पहचान देगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी ताकत लगाने की अपील की। लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन राज्य के लिए गौरव का विषय है। राजग के सभी घटक दल पूरी एकजुटता के साथ इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार को विकास की नई गति मिली है। कार्यकर्ता गांव और प्रखंड स्तर पर लोगों को कार्यक्रम से जोड़कर इसे ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे।

स्वदेशी विचार गोष्ठी : आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही राष्ट्र होगा सशक्त : दिलीप निराला

भागलपुर। स्वदेशी जागरण मंच, भागलपुर इकाई की ओर से श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी की जयंती के अवसर पर मंगलवार को स्थानीय श्री श्री गौशाला परिसर में 'आर्थिक राष्ट्रवाद एवं आत्मनिर्भर भारत' विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। गोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मंच के पूर्व प्रांत संयोजक दिलीप निराला ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक मजबूती के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को केवल एक बड़े उपभोक्ता बाजार के बजाय उत्पादन, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वदेशी किसी के विरोध का नहीं, बल्कि अपने देश की क्षमता, प्रतिभा और संसाधनों पर विश्वास का विचार है। विकास का वास्तविक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। विशिष्ट अतिथि भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश लाल ने राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में संगठित श्रमिक शक्ति के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती में श्रमिकों की भूमिका अहम है और विकास की प्रक्रिया में उनके सम्मान व सामाजिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे पूर्व, स्वागत भाषण में जिला संयोजक रंजीत कुमार राय ने कहा कि आर्थिक राष्ट्रवाद का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं, बल्कि नीतियों और उत्पादन में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना है। उन्होंने भागलपुर के प्रसिद्ध रेशम उद्योग और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित कर जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया तथा स्वदेशी को दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का मंच संचालन जिला सहसंयोजक डॉ. सुभांकर सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन एवं समापन भाषण विभाग संयोजक निर्दोष कुमार मिश्रा ने दिया। उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद को जन-आंदोलन बनाने की आवश्यकता जताई। इस अवसर पर मीडिया प्रमुख इंदु भूषण झा, राजेश टंडन, प्रकाश झा, संजीव चौधरी, चंदन कुमार, रौनक कुमार सिंह, डॉ. कृष्ण बिहारी, डॉ. दीपक कुमार झा, श्रीराम राय, अशोक सिंह, विजय कनौजिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

वाटर मेट्रो के शुभारंभ से गंगा नदी में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन तथा जल परिवहन को मिलेगी नई पहचान : सम्राट चौधरी

पटना,एजेंसी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना के दीघा घाट से कंगन घाट तक कैटामरान वेसल (वाटर मेट्रो) का शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई सुविधा से पटना आनेवाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को गंगा नदी में जलयात्रा का नया अनुभव मिलेगा। साथ ही, राजधानी में पर्यटन की संभावनाओं को और मजबूती मिलेगी। पर्यटन विभाग की यह पहल गंगा नदी में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों को आधुनिक एवं सुविधाजनक जल परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वाटर मेट्रो के शुभारंभ होने से पटनावासियों को अशोक राजपथ के ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और गंगा के रास्ते सुगम और सुविधाजनक सफर का विकल्प मिलेगा।



ज्ञातव्य है कि कैटामरान वेसल 50 यात्रियों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जलयान है। यह मुख्यत: विद्युत ऊर्जा से संचालित होता है। इसके संचालन से जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण नहीं होगा। यह गंगा नदी में पर्यटकों को एक रोमांचक एवं सुखद यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। इस कैटामरान वेसल में उद्घोषणा प्रणाली, वातानुकूलन सुविधा, शौचालय, व्हील चेयर एवं अन्य आवश्यक आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कैटामरान वेसल (वाटर मेट्रो) का परिचालन पटना के दीघा (मीनार घाट) से प्रारंभ होगा तथा यह गांधी घाट पहुँचेगा। इसके पश्चात् गांधी घाट से पुन: दीघा के लिए प्रस्थान करेगा तथा शाम को दीघा (मीनार घाट) पहुँचेगा। इस आधुनिक कैटामरान वेसल में यात्रा का किराया प्रति वयस्क 50 रूपये निर्धारित किया गया है। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यात्रा नि:शुल्क होगी, जबकि पाँच से बारह वर्ष तक के बच्चों के लिए टिकट का दर निर्धारित किराये का आधा होगा। सभी पर्यटक अभी दीघा घाट पर काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं, शीघ्र ही ऑनलाइन टिकट की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। यह कैटामरान वेसल हाइब्रिड इंजन से लैस है। इसमें उपलब्ध बैटरी को चार्ज करने के लिए पटना के दीघा (मीनार घाट) एवं गांधी घाट पर फास्ट चार्जर एवं शोर चार्जर की व्यवस्था की गई है। भविष्य में इसका संचालन कंगन घाट तक विस्तारित किया जायेगा। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, विधायक संजीव चौरसिया, विधायक रत्नेश कुमार, विधायक संजय कुमार, पटना की महापौर सीता साहू, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी0 कार्तिकेय धनजी, पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा, जिलाधिकारी कुंदन कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के0 शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

जेन जेड के हाथों स्थानीय बाजारों का डिजिटलीकरण, रोजगार का मॉडल बना रही सॉफ्टा

पटना,एजेंसी। बिहार में स्थानीय बाजारों का डिजिटलीकरण युवाओं के रोजगार का आधार बने और छोटे कारोबार डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बना सकें, इसी सोच के साथ सॉफ्टा टेक्नोलॉजीज अपने सोशल प्लेटफॉर्म जेडकेटीओआर (ZKTOR) का विस्तार कर रही है। छोटे शहरों और कस्बों से शुरू इस पहल में कंपनी चाहती है कि जेन ज़ेड पीढ़ी बिखरे हुए पारंपरिक बाजारों को डिजिटल बनाने का नेतृत्व करे, उन्हें सहेजे और इसी प्रक्रिया में अपने लिए आजीविका तैयार करे।

सोशल मीडिया, लोकल मीडिया, विज्ञापन और ई-कॉमर्स को आगे बढ़ाना, छोटे उद्यमों का डिजिटलीकरण करना, उन्हें प्लेटफॉर्म से जोड़ना और ऑनलाइन सेवाओं के इस्तेमाल में मदद देना युवाओं के काम का हिस्सा होगा। वीडियो, फोटो, एंटरटेनमेंट और नॉलेज से जुड़े कंटेंट के जरिए दर्शक जुटाने वाले क्रिएटर्स के लिए भी मोनेटाइजेशन का रास्ता है। कंपनी के मुताबिक, जेडकेटीओआर क्रिएटर्स को उनके कंटेंट से होने वाली किसी भी तरह की इनकम का 70 प्रतिशत शेयर सीधे देगा। स्थानीय कारोबारों की डिजिटल जरूरतों से लेकर कंटेंट के जरिए कमाई तक, इस मॉडल का उद्देश्य युवाओं के लिए अपने क्षेत्र में रोजगार और भागीदारी के अवसर तैयार करना है। कंपनी के संस्थापक और सीईओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि यह सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटी को हाइपरलोकल स्तर



पर जोड़ने का प्रयास है, जिसमें स्थानीय लोग कंटेंट बनाने और कनेक्टेड रहने से लेकर कारोबारों तथा सेवाओं के संचालन तक में भागीदार हों। कंपनी इस स्थानीय डिजिटल इकोसिस्टम को अगले 5 से 7 वर्षों में देश के हर जिले तक पहुंचाना चाहती है। इसमें स्थानीय खबरें, आसपास की रेलेवेंट जानकारियां, एजुकेशनल, सिविल और प्रशासनिक सूचनाएं, लोकल एग्जाम और जॉब्स से जुड़ी जानकारी प्राथमिकता पर उपलब्ध होंगी।

लोकल एमएसएमई और ग्रामीण ई-कॉमर्स के उत्पाद तथा सेवाएं खोजी जा सकेंगी, जबकि विज्ञापन के जरिए कारोबारी आसपास के ग्राहकों तक पहुंच सकेंगे। आम जनता, कारोबारियों, प्रशासन और स्थानीय सोसाइटीज को एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़कर स्थानीय सेवाओं, रोजगार और इकोनॉमी को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। हाइपरलोकल टेक्नोलॉजी के तहत महाराष्ट्र के नाशिक से इस्तेमाल करने वाले यूजर को वहां की खबरें और रेलेवेंट कंटेंट प्रायोरिटी में दिखते हैं। इसी तरह बिहार के यूजर को उसके अपने क्षेत्र की खबरों और जानकारी में प्राथमिकता मिलती है। इस नेटवर्क के केंद्र में जेडकेटीओआर का ऑल इन वन सुपर सोशल मीडिया ऐप है, जिसमें स्टेटस, फीड्स, नेटवर्किंग, शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो प्लेटफॉर्म, चैनल्स, क्लिप्स, पेजेज और कम्युनिकेशन की सुविधाएं एक ही जगह मौजूद हैं। कंपनी के अनुसार, मास पब्लिक बीटा टेस्टिंग के दौरान कुछ ही महीनों में प्लेटफॉर्म ने एक मिलियन से ज्यादा यूजर्स का माइलस्टोन पार कर लिया है। इस्तेमाल का अनुभव पारंपरिक सोशल मीडिया जैसा है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इसकी व्यवस्था बिहेवियर ट्रैकिंग या एल्गोरिदम के जरिए फीड पुश करने पर आधारित नहीं है। जीरो नॉलेज सर्वर आर्किटेक्चर, जीरो बिहेवियरल ट्रैकिंग, नो प्रोफाइलिंग और नो यूआरएल टेक्नोलॉजी को सॉफ्टा प्राइवेसी एंड डाटा सेफ्टी बाई डिजाइन की बुनियाद बताती है। इसका उद्देश्य डेटा का मिसयूज रोकना, ऑनलाइन आजादी और डिजिटल डिग्निटी को सुरक्षित रखना तथा उन लोगों को भी अधिकतम प्राइवेसी और सुरक्षा देना है, जिन्हें प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी की जानकारी नहीं है। ऐप में सॉफ्टा द्वारा विकसित टोला एआई की वीडियो डिटेक्टिंग लेयर, वीडीएल, भी मौजूद है। कंपनी के मुताबिक, यह अनसोशल और नग्नता वाले कंटेंट की स्वत: पहचान कर प्लेटफॉर्म को साफ-सुथरा रखने में मदद करती है।

सीताराम विवाह महोत्सव की तैयारियां शुरू, कल्लू राय और बबली दुबे बने राजाराम बाबा के प्रतिनिधि

बक्सर,एजेंसी। नया बाजार स्थित श्री सीताराम विवाह महोत्सव आश्रम में सिय-पिय मिलन महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस वर्ष महोत्सव में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा मुख्य आकर्षण होगी। वे 13 से 16 दिसंबर तक बक्सर में कथा सुनाएंगे। श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए कथा का आयोजन हवाई अड्डा परिसर में किया जाएगा। वहीं, अन्य धार्मिक कार्यक्रम आश्रम परिसर और नेत्र अस्पताल के समीप मैदान में आयोजित होंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को आश्रम परिसर में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता महंत राजाराम शरण दास जी महाराज ने की, जबकि संचालन डॉ. रामनाथ ओझा ने किया। महंत जी ने बताया कि महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार के 57वें निर्वाण दिवस एवं श्रीराम-जानकी के 25वें पाटोत्सव के अवसर पर 7 से 16 दिसंबर तक दस दिवसीय महोत्सव आयोजित होगा।

इसमें श्रीराम कथा, श्रीकृष्ण लीला, रामलीला, सत्संग, संकीर्तन और श्रीसीताराम विवाह महोत्सव सहित कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। आचार्य मिथिलेशनंदिनी शरण जी महाराज 7 से 12 दिसंबर तक श्रीराम कथा सुनाएंगे। इसके बाद 13 से 16 दिसंबर तक आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा होगी। महंत राजाराम शरण दास जी महाराज ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए व्यवस्थाएं करना चुनौतीपूर्ण है। बक्सर की धार्मिक परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सभी सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट होकर सहयोग करना होगा।

उन्होंने समाजसेवी कल्लू राय और बबली दुबे को संयुक्त रूप से अपना प्रतिनिधि घोषित करते हुए आयोजन की तैयारियों और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही जिलेवासियों से दोनों को सहयोग देने की अपील की। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह छह से नौ बजे तक श्रीरामचरितमानस का सामूहिक नवाह पारायण, सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक श्रीकृष्ण लीला और रात आठ से बारह बजे तक रामलीला का मंचन होगा। दमोह की संकीर्तन मंडली नौ दिवसीय अष्टयाम श्रीहरिनाम संकीर्तन करेगी। 12 दिसंबर को पुष्पवाटिका लीला और धनुष यज्ञ, 13 दिसंबर को मटकोर एवं श्रीराम बारात शोभायात्रा, 14 दिसंबर को शाम सात बजे श्रीसीताराम विवाह महोत्सव और 15 दिसंबर को श्रीराम कलेवा का आयोजन होगा। बैठक में राजपुर विधायक संतोष कुमार निराला, चेयरमैन प्रतिनिधि नियामतुल्लाह फरीदी, व्यवसायी अशोक सर्राफ, वैष्णवी ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप राय, पार्षद इंद्र प्रताप सिंह, राघवेंद्र राय, ओम जी यादव, नंदू पांडेय, रेडक्रॉस अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, सचिव डॉ. श्रवण तिवारी सहित आयोजन समिति के सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे।

एक नजर

बारिश के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा एकदिवसीय मैच रद्द



हैमिल्टन,एजेंसी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबला लगातार बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। अंपायरों ने मौसम और मैदान की स्थिति का जायजा लेने के बाद मंगलवार को खेल नहीं कराने का फैसला किया। इसके बाद दोनों टीमों के कप्तानों को निर्णय की जानकारी दी गई और खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाकर मुकाबला समाप्त होने की औपचारिकता पूरी की। हालांकि बारिश कुछ देर के लिए जरूर रुकी थी, जिसके बाद टॉस भी हुआ था और भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद बारिश फिर शुरू हो गई। अंपायरों ने काफी इंतजार करने के बाद आखिरकार मैच रद्द करने का फैसला किया। मैच अधिकारियों के अनुसार, लगातार हुई बारिश के कारण मैदान को खेलने लायक बनाने में कम से कम 30 से 40 मिनट का समय लगना था। इसके बावजूद मौसम में सुधार नहीं हुआ और अंतत: मुकाबला रद्द करने का फैसला लिया गया। मैच रद्द होने के बाद पांच मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है। इस नतीजे के साथ भारतीय टीम अब सीरीज नहीं हार सकती। न्यूजीलैंड के पास सीरीज बराबर करने का मौका जरूर है, लेकिन इसके लिए उसे बाकी दोनों मुकाबले जीतने होंगे।

भारत के 100वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने अनुज श्रीवात्री, प्रधानमंत्री ने दी बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को अनुज श्रीवात्री को भारत का 100वां शतरंज ग्रैंडमास्टर बनने पर बधाई दी। उन्होंने इस उपलब्धि को भारतीय शतरंज के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए कहा कि यह देश में खेल की बढ़ती लोकप्रियता और युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में लिखा, 'भारत ने शतरंज में शतक लगा दिया है! है न यह शानदार उपलब्धि ? भारत अब 100 शतरंज ग्रैंडमास्टर वाला देश बन गया है। भारत के 100वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बनने पर अनुज श्रीवात्री को बधाई! यह कितनी शानदार उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत का 100 ग्रैंडमास्टर तक पहुंचना खिलाड़ियों की अपार प्रतिभा, समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ देश के युवाओं में शतरंज की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह देखकर विशेष खुशी होती है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से युवा शतरंज प्रतिभाएं उभर रही हैं और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रही हैं। उम्मीद है कि यह उपलब्धि और अधिक युवाओं को शतरंज अपनाने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। मध्य प्रदेश के अनुज श्रीवात्री ने रविवार को सातवीं आसियान प्लस व्यक्तिगत ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव हासिल किया। वह मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। अनुज ने शुरुआती दौर में हार के बाद शानदार वापसी की। उन्होंने अपने अंतिम आठ मुकाबलों में सात अंक हासिल किए और टूर्नामेंट का खिताब जीतने के साथ ग्रैंडमास्टर का दर्जा प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि से भारतीय शतरंज में एक नया अध्याय जुड़ गया है। देश के शतरंज प्रेमियों को लंबे समय से 100वें ग्रैंडमास्टर का इंतजार था। वहीं, मध्य प्रदेश को भी अपने पहले ग्रैंडमास्टर का इंतजार था, जिसे अनुज ने पूरा कर दिया।

जापान मास्टर्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं त्रीसा-गायत्री की जोड़ी



कुमामोटो। भारतीय महिला युगल जोड़ी त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जापान मास्टर्स 2026 के दूसरे दौर में जगह बना ली है। मंगलवार को कुमामोटो प्रीफेक्चरल जिम्नेजियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने जापान की हिनाता सुजुकी और नाओ यामाकिता को सीधे गेमों में हराया। त्रीसा और गायत्री ने पहला गेम 21-17 से अपने नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में भी भारतीय जोड़ी ने अपना दबदबा बनाए रखा और 21-14 से जीत दर्ज की। यह मुकाबला 42 मिनट तक चला। इस जीत के साथ दोनों ने प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पुरुष युगल में हरिहरन अमसकरुणन और अर्जुन एमआर को पूर्व विश्व चैंपियन मलेशियाई जोड़ी आरोन चिया और सोह वूई यिक के खिलाफ वॉकओवर मिला। मुकाबले के पहले गेम में भारतीय जोड़ी 11-6 से आगे थी, तभी मलेशियाई खिलाड़ियों ने चोट या अन्य कारणों का उल्लेख किए बिना मुकाबले से हटने का फैसला किया। इससे पहले दिन में मिश्रित युगल जोड़ी ध्रुव कपिला और राधिका शर्मा को क्वालीफिकेशन दौर में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को अमेरिका की चेन झी यी और फ्रांसेस्का कॉर्बेट ने सीधे गेमों में हराया। पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने 8-8 तक कड़ी टक्कर दी। हालांकि, ब्रेक तक अमेरिकी जोड़ी ने 11-9 की बढ़त बना ली और इसके बाद लगातार अंक जुटाते हुए गेम 21-16 से जीत लिया। दूसरा गेम अधिक संघर्षपूर्ण रहा। भारतीय जोड़ी ने वापसी करते हुए स्कोर 14-14 से बराबर कर दिया, लेकिन इसके बाद चेन और फ्रांसेस्का ने लगातार अंक हासिल किए और 21-15 से गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय हॉकी टीम घोषित, सलीमा टेटे संभालेंगी कप्तानी

नई दिल्ली,एजेंसी। हॉकी इंडिया ने मंगलवार को मध्य प्रदेश महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल 2026 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी। मिडफील्डर सलीमा टेटे टीम की कप्तानी जारी रखेंगी। यह टीम पिछले महीने जापान में हुए एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलेगी। टूर्नामेंट का आयोजन 19 से 28 नवंबर तक भोपाल के नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर, नाथू बरखेड़ा में किया जाएगा। मेजबान भारत मौजूदा चैंपियन होने के साथ तीन बार इस खिताब को जीत चुका है। भारतीय टीम ने 2016, 2023 और 2024 में यह ट्रॉफी अपने नाम की थी। अब उसकी नजर लगातार तीसरी और कुल चौथी बार चैंपियन बनने पर होगी।



इस छह देशों के टूर्नामेंट में भारत के अलावा चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया की टीमें हिस्सा लेंगी। भारत की तरह दक्षिण कोरिया भी तीन बार यह खिताब जीत चुका है। प्रतियोगिता राउंड रॉबिन प्रारूप में खेली जाएगी। प्रत्येक टीम लीग चरण में अन्य पांच टीमों से एक-एक बार भिड़ेगी। लीग चरण के बाद शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। मुख्य कोच सजॉर्ड मारिजने ने कहा, 'यह मेरे लिए अन्य खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देने का समय है। कुछ खिलाड़ी अपनी सामान्य भूमिका से अलग स्थानों पर खेलेंगी, ताकि मैं देख सकूं कि वे नई भूमिका में कैसा प्रदर्शन करती हैं। हम घरेलू दर्शकों के सामने खेलने और साल का शानदार अंत करने के लिए उत्साहित हैं।

टूर्नामेंट के पहले दिन एशिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम चीन का सामना थाईलैंड से होगा। उद्घाटन समारोह के बाद भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत मलेशिया के खिलाफ करेगी। भारत का दूसरा मुकाबला 21 नवंबर को दक्षिण कोरिया से, तीसरा मुकाबला 22 नवंबर को थाईलैंड से, चौथा मुकाबला 24 नवंबर को चीन से और लीग चरण का अंतिम मैच 25 नवंबर को जापान के खिलाफ होगा। सेमीफाइनल मुकाबले 27 नवंबर को और पदक के लिए मुकाबले 28 नवंबर को खेले जाएंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप टिर्की ने कहा, 'मध्य प्रदेश महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल 2026 हमारी टीम के लिए एशियाई खेलों की ऐतिहासिक जीत की लय को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। घरेलू समर्थकों के सामने खेलना खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा होगी। मुझे विश्वास है कि खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगी और देश को गौरवान्वित करेंगी।' हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने भी टीम को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, 'हमें खुशी है कि मध्य प्रदेश एशिया की कुछ बेहतरीन हॉकी टीमों की मेजबानी करने जा रहा है। हमारी महिला टीम का साल शानदार रहा है, जिसमें एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक सबसे बड़ी उपलब्धि रहा। यह टूर्नामेंट खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का एक और अवसर देगा। मौजूदा चैंपियन होने के नाते टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध होगी। हमें रोमांचक मुकाबलों और मध्य प्रदेश के हॉकी प्रशंसकों के मजबूत समर्थन की उम्मीद है।'

बारिश ने चौथे दिन का खेल धोया, भारत ए-न्यूजीलैंड ए के बीच ड्रॉ रही टेस्ट सीरीज

लिंकन। भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेली गई तीन मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला भी ड्रॉ पर समाप्त हो गया। चौथे दिन बारिश के कारण खेल नहीं हो सका और इसके साथ ही पूरी सीरीज भी बराबरी पर खत्म हुई। चार दिवसीय तीनों मुकाबलों में कोई नतीजा नहीं निकल सका।

मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ए ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 36 रन बनाए थे। डीन फॉक्सक्रॉफ्ट 10 और जैक गिब्सन एक रन बनाकर नाबाद थे। न्यूजीलैंड ए को जीत के लिए अभी 428 रन की जरूरत थी। इससे पहले न्यूजीलैंड ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारत ए ने पहली पारी में पांच विकेट पर 464 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत की थी। टीम को यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 175 रन की शानदार साझेदारी दिलाई। जायसवाल ने 138 गेंदों पर 16 चौकों और दो छक्कों की मदद से 102 रन बनाए, जबकि सुदर्शन ने 215 गेंदों पर 11 चौकों की सहायता से 88 रन की पारी खेली। इसके बाद तिलक वर्मा ने 164 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 81 रन बनाए। कप्तान ध्रुव जुरेल ने 95 गेंदों पर नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 71 रन जोड़े। वहीं, वाशिंगटन सुंदर 107 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड ए की ओर से जैक गिब्सन ने दो विकेट लिए। आगामी 19 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले भारत ए के बल्लेबाजों का प्रदर्शन सकारात्मक रहा। देवदत्त पडिक्कल तीन मैचों की पांच पारियों में 65.20 की औसत से 326 रन बनाकर टीम के शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया। यशस्वी जायसवाल ने तीन मैचों की पांच पारियों में 69.75 की औसत से 279 रन बनाए।

उन्होंने दो शतक लगाए और शुरुआती कुछ पारियों में कम स्कोर के बाद लगातार दो शतक जड़े। साई सुदर्शन ने 46.20 की औसत से 231 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल रहे। कप्तान ध्रुव जुरेल ने चार पारियों में 44.75 की औसत से 179 रन बनाए। उनके नाम एक शतक और एक अर्धशतक रहा। बिना अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले बल्लेबाज यश राठौड़ का प्रदर्शन भी भारत ए के लिए सकारात्मक रहा। उन्होंने दो मैचों में 111.50 की औसत से 223 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। गेंदबाजी में औकिब नबी ने एक मैच में छह विकेट, जबकि मोहम्मद सिराज ने एक मैच में चार विकेट लेकर प्रभावित किया।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्रमुख ग्रीनबर्ग ने सैंडपेपर विवाद की जांच दोबारा शुरू करने से किया इनकार

सिडनी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख टॉड ग्रीनबर्ग ने मंगलवार को 2018 के चर्चित सैंडपेपर विवाद की जांच दोबारा शुरू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नए सिरे से जांच कराने की कोई ठोस वजह नजर नहीं आती।

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा में दावा किया है कि 2018 में गेंद से छेड़छाड़ की योजना के बारे में पूरी टीम को जानकारी थी और यह मामला केवल कुछ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं था। मंगलवार को जारी हुई उनकी किताब के बाद इस विवाद पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। उस समय दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था, ताकि गेंद को रिवर्स स्विंग मिल सके। ग्रीनबर्ग ने स्थानीय रेडियो स्टेशन एसईएन से बातचीत में कहा कि खिलाड़ियों के इस मामले को लेकर ख्वाजा के दावे से बिल्कुल अलग विचार हैं। उन्होंने कहा, 'उनकी किताब में कुछ खास विवरण ऐसे हैं, जो दूसरे लोगों द्वारा दिए गए बयानों से मेल नहीं खाते। हालांकि, हमें मिली जानकारी के आधार पर हम जांच के नतीजे से संतुष्ट हैं। इसमें वह जानकारी भी शामिल है, जो हमने उस्मान से देखी है। इस मामले पर हमारा रुख नहीं बदला है। हमें जांच दोबारा शुरू करने या इस मामले की फिर से समीक्षा करने की कोई ठोस वजह नजर नहीं आती।

मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से कुछ हासिल होगा। इस मामले के समय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे जेम्स सदरलैंड ने मंगलवार को टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं, 2019 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने भी सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से इस बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया। बैनक्रॉफ्ट ने 2021 में 'द गार्जियन' को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि यह बात अपने आप स्पष्ट थी कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के अलावा टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी गेंद से छेड़छाड़ की योजना की जानकारी थी। गेंद से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, उपकप्तान डेविड वार्नर और बैनक्रॉफ्ट को अपमानजनक परिस्थितियों में स्वदेश लौटना पड़ा था।

विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, 65 देशों में पांचवां स्थान हासिल किया

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत ने 47वीं विश्व आर्म रेसलिंग और 28वीं विश्व पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 65 देशों के बीच पांचवां स्थान हासिल किया। नई दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 59 पदक जीते, जिनमें नौ स्वर्ण, 19 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं। पीपुल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (पीएएफआई) और प्रो पंजा लीग ने वर्ष 2026 के लिए शीर्ष 10 में जगह बनाने और अगले तीन वर्षों में शीर्ष पांच में पहुंचने का लक्ष्य रखा था। भारतीय खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि निर्धारित समय से तीन साल पहले ही हासिल कर ली।



भारतीय दल के प्रदर्शन में पैरा खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही। उन्होंने दो स्वर्ण, 10 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 26 पदक जीते। इस प्रदर्शन के साथ भारत पैरा वर्ग की पदक तालिका में पांचवें स्थान पर रहा। सब-जूनियर, जूनियर और युवा वर्ग के खिलाड़ियों ने तीन स्वर्ण, आठ रजत और नौ कांस्य सहित 20 पदक जीते। मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों को चार स्वर्ण, एक रजत और सात कांस्य सहित 12 पदक मिले। सीनियर वर्ग में भारत ने एक कांस्य पदक हासिल किया। ग्रैंड मास्टर महिला 80 किलोग्राम वर्ग में जिन्सीमोल सेबेस्टियन ने दोनों हाथों से स्वर्ण पदक जीते। योगेश चौधरी और शौकत वीटी ने भी दाएं हाथ से स्वर्ण और बाएं हाथ से कांस्य पदक हासिल किया। सीनियर महिला 70 किलोग्राम वर्ग में मधुरा केएन ने दाएं हाथ की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। प्रो पंजा लीग की सह-संस्थापक प्रीति झांगियानी और परवीन डबास ने भारत में आर्म रेसलिंग को पेशेवर स्वरूप देने और जमीनी स्तर से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थित मंच तैयार करने की पहल की है। पीएएफआई की अध्यक्ष और एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन की उपाध्यक्ष प्रीति झांगियानी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार इस विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की। भारतीय खिलाड़ियों को रूस, कजाकिस्तान, बुल्गारिया, तुर्किये, जॉर्जिया, घाना और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के प्रमुख आर्म रेसलिंग देशों के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला। प्रो पंजा लीग के सह-संस्थापक परवीन डबास ने कहा, 'दुनिया में पांचवां स्थान हासिल करना हमारे दो शानदार खिलाड़ी समूहों- पैरा आर्म रेसलिंग खिलाड़ियों और सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों की उपलब्धि है। हमारे पैरा खिलाड़ियों ने भारत के कुल पदकों में लगभग आधे पदकों का योगदान दिया और पैरा तथा सामान्य वर्ग की तालिका में देश को पांचवें स्थान पर पहुंचाने में भूमिका निभाई। जूनियर, मास्टर्स और सीनियर खिलाड़ियों ने भी हर मुकाबले में इसी जज्बे का प्रदर्शन किया। हमने तीन साल के भीतर शीर्ष पांच में पहुंचने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इन खिलाड़ियों ने इसी साल यह उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने साबित किया है कि भारतीय आर्म रेसलिंग के हर वर्ग में दमदार प्रतिभा मौजूद है। पीएएफआई की अध्यक्ष, एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन की उपाध्यक्ष और प्रो पंजा लीग की सह-संस्थापक प्रीति झांगियानी ने कहा, 'विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करना भारत के लिए सम्मान की बात थी। कुल मिलाकर पांचवां स्थान हासिल करना फेडरेशन की ओर से किए जा रहे प्रयासों की बड़ी उपलब्धि है।

भारत के बेंगलुरु में नेपाल की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम खेलेगी टी-20 सीरीज, सोनी पाखिन संभालेंगी कप्तानी



काठमांडू,एजेंसी। नेपाल क्रिकेट संघ (सीएएन) ने भारत के बेंगलुरु में होने वाली नेपाल-भारत अंडर-19 महिला टी-20 क्रिकेट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय नेपाली टीम की घोषणा कर दी है। यह सीरीज 12 से 22 नवंबर तक आयोजित होगी। सीएएन की ओर से घोषित टीम की कमान सोनी पाखिन को सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में नेपाली अंडर-19 महिला टीम भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज में मैदान पर उतरेगी। इस सीरीज का उद्देश्य युवा महिला क्रिकेटरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्रदान करना और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को विकसित करना है। भारत में होने वाले इन मुकाबलों से नेपाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और मजबूत क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलने का अवसर मिलेगा।

नेपाल की 15 सदस्यीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम:

सोनी पाखिन (कप्तान)
रचना कुमारी चौधरी
रिया शर्मा
प्रिन्सा राना मगर
टीका साह
अंजिला पाठक
साक्षी यादव
सावित्री धामी
मनीषा चौधरी
आशिका कुमारी महरा
आस्था चौधरी
प्रथा श्रेष्ठ

ज्योत्स्निका मरासिनी
पूर्णिमा राजवंशी
तिर्सना विश्वकर्मा

नेपाल क्रिकेट संघ को उम्मीद है कि इस सीरीज के जरिए युवा महिला खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने और भविष्य की राष्ट्रीय टीम के लिए खुद को तैयार करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा।

विश्व स्कूल गोल्फ चैंपियनशिप में देवव्रत ने जीता कांस्य, भारत पांचवें स्थान पर

मोरक्को। अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल संगठन (आईएसएसओ) की भारतीय टीम ने मोरक्को में आयोजित विश्व स्कूल गोल्फ चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय गोल्फर देवव्रत ने अंडर-15 वर्ग में कांस्य पदक जीता, जबकि टीम स्पर्धा में भारतीय दल पांचवें स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में दुनिया भर की 19 टीमों ने हिस्सा लिया। टैगाजाउट-अगादिर में 2 से 8 नवंबर तक आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत की ओर से छह छात्र-गोल्फरों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला।

देवव्रत का कांस्य पदक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आया। प्रतियोगिता के दौरान तेज हवाओं और लगातार बारिश ने खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। ऐसे हालात में देवव्रत ने शानदार संयम और दृढ़ता का परिचय दिया। उन्होंने फ्रंट नाइन में तीन अंडर पार का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर जगह बनाई। टीम स्पर्धा में भारत का पांचवां स्थान हासिल करना भी महत्वपूर्ण रहा। छह भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया की अन्य स्कूल टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अनुभव मिला, जो उनके खेल विकास के लिए उपयोगी साबित होगा। आईएसएसओ की निदेशक आकांक्षा थापाक ने टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा, 'देवव्रत का कांस्य पदक आईएसएसओ और भारतीय स्कूल खेलों के लिए गर्व का क्षण है। आईएसएसओ में हम युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे अनुभव खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाने, उनके कौशल को निखारने और उन्हें आगे की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। पूरे भारतीय दल को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई। यह चैंपियनशिप आईएसएसओ के लिए स्कूली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय खेल मंच उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण अवसर रही। इससे खिलाड़ियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का अनुभव हासिल करने, दूसरे देशों के खिलाड़ियों के साथ खेल संबंध विकसित करने और अपने खेल में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए जरूरी कौशल तथा आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका मिला।

क्या है आईएसएसओ

इंटरनेशनल स्कूल्स स्पोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन (आईएसएसओ) एक प्रमुख खेल संचालन संस्था है, जो भारत में इंटरनेशनल स्कूलों के छात्रों के लिए व्यवस्थित प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध कराने और खेल कौशल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अपनी राष्ट्रीय चैंपियनशिप और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के अवसरों के माध्यम से आईएसएसओ का उद्देश्य युवा खेल प्रतिभाओं को निखारना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और छात्रों के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने के रास्ते बनाना है ताकि वे प्रतिष्ठित खेल मंचों पर अपने स्कूल और देश का प्रतिनिधित्व कर सकें।

एक नजर

जलवायु परिवर्तन से पहाड़ी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अनुकूलन वित्त बढ़ाना जरूरी : खनाल



काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अनुकूलन वित्त जुटाने और उस तक पहुंच आसान बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए पर्वतीय देशों को पर्याप्त और सुलभ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है। विदेशमंत्री खनाल ने तुर्किये के अंताल्या में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 31वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान आयोजित एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। 'अनुकूलन वित्त के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों की सहनशीलता मजबूत करना' शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन नेपाल, भूटान और किर्गिस्तान ने किया था। इसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और जॉय एनवायरनमेंट नेटवर्क ने सहयोग किया। खनाल ने हाल ही में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ को 'हिमालयी सुनामी' बताते हुए उससे हुए आर्थिक, भौतिक और मानवीय नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों से पर्वतीय क्षेत्रों को सुरक्षित रखने और उनकी आपदा से उबरने की क्षमता मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर एकजुटता और सहयोग जरूरी है। खनाल ने कहा कि दुनिया की लगभग एक-तिहाई आबादी प्रत्यक्ष रूप से पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा और उनके संरक्षण को संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन के क्षेत्र में वित्तीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। खनाल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऐसी जलवायु वित्त व्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया, जिसके तहत पर्याप्त, अनुमानित और आसानी से उपलब्ध वित्तीय संसाधन सुनिश्चित किए जा सकें। विदेशमंत्री ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को हासिल करने की संभावनाएं बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ठोस सहयोग और वित्तीय प्रतिबद्धता दिखानी होगी।

नेपाल में सात माह में नहीं हो सकी आयोगों में नई नियुक्ति

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल में संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग और बेपता पारिएका व्यक्तियों के लिए बने जांच आयोगों पिछले सात महीनों से पदाधिकारियों के बिना चल रहे हैं। सरकार ने 5 मई 2026 को 'सार्वजनिक पदाधिकारियों को पदमुक्त करने संबंधी विशेष प्रावधान अध्यादेश, 2026' जारी किया था। इस के तहत दोनों आयोगों के तत्कालीन पदाधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया था। तब से नई नियुक्ति नहीं हो पाई है। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग में शुरुआत में 63,718 शिकायतें दर्ज हुई थीं। वर्ष 2024 में संबंधित कानून में संशोधन के बाद शिकायतें दर्ज कराने की समय-सीमा बढ़ा दी गई । इसके बाद 15 हजार से अधिक नई शिकायतें दर्ज हुईं। शिकायतों की कुल संख्या 78,909 हो गई। राष्ट्रीय सभा के सदस्य और पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती ने कहा, 'आयोगों में कोई पदाधिकारी नहीं हैं, जबकि वहां काफी काम किया जाना बाकी है। आयोगों का पुनर्गठन होना चाहिए, शिकायतों की जांच होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।' खाती राष्ट्रीय सभा की विधायन व्यवस्थापन समिति के तहत गठित उपसमिति द्वारा किए गए उस अध्ययन में भी शामिल थे, जिसमें कानूनों के कार्यान्वयन और संक्रमणकालीन न्याय की मौजूदा स्थिति का आकलन किया गया । इस अध्ययन में पाया गया कि सरकार ने संक्रमणकालीन न्याय के मुद्दे को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी है। खाती ने कहा, 'कानून और कार्यविधि बनाने के साथ-साथ राजनीतिक सहमति कायम करना, आयोगों की संस्थागत क्षमता मजबूत करना और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करना भी आगे की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। लेकिन एक बार फिर ऐसा नहीं दिख रहा है कि सरकार ने इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में रखा है।' उन्होंने कहा कि कानून एवं न्याय मंत्री ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन सरकार ने अब तक अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

बांग्लादेश में मदरसा और मकान में लगी आग, धुएं की चपेट में आए 48 छात्र बेहोश

ढाका (बांग्लादेश)। देश में दो स्थानों पर लगी आग में बड़ी अनहोनी टल गई। हालांकि एक मदरसा में आग लग जाने से कम से कम 48 छात्र धुएं की चपेट में आने से बेहोश गए। दूसरी घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर लिखे जाने तक दोनों जगह आग बुझाई जा चुकी थी। छात्रों को अस्पताल ले जाया गया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पहली घटना सोमवार और मंगलवार की रात करीब 1:55 बजे नारायणगंज के फतुल्लाह इलाके के साइनबोर्ड स्थित जामिया अशरफिया मदरसा हुई। यहां ग लगने के बाद धुएं की चपेट में आने से कम से कम 48 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से तीन छात्र गंभीर हालत में इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। दमकल विभाग ने चार घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के रेजिडेंट फिजिशियन सुल्तान महमूद सिकदर ने बताया कि धुएं के कारण बेहोश हुए 48 छात्रों को अस्पताल लाया गया है। इनमें से तीन की हालत गंभीर है। आईसीयू में भर्ती छात्रों के नाम यूसुफ (18), खैरुल (22) और जुबैर (18) हैं। दमकल विभाग के अधिकारी शाहजहां ने बताया कि तड़के 3:44 बजे आग पर काबू पा लिया गया। आग पांच मंजिला मदरसा इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी थी। अस्पताल में इलाज करा रहे छात्रों ने बताया कि दूसरी मंजिल पर बनी लाइब्रेरी थी पूरी तरह जल गई है। प्रभावित छात्रों के हवाले से चिकित्सक सुल्तान महमूद सिकदर ने बताया कि माना जा रहा है कि आग मदरसे के एक हिस्से में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। धुआं पूरी इमारत में तेजी से फैल गया, जिससे छात्रों के बीच अफरा-तफरी मच गई। बाहर निकलने की जल्दबाजी में वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। धुएं की वजह से कई छात्रों के श्वसन तंत्र (सांस लेने के रास्ते) को नुकसान पहुंचा है। दूसरी घटना मंगलवार सुबह कॉक्स बाजार शहर के कलाटोली होटल-मोटेल जोन में हुई। यहां एक होटल के बगल में बने मकान में आग लग गई। आग सुबह करीब 6 बजे कलाटोली के शैकतपारा रोड पर लगी।

अबू धाबी में रूस, अमेरिका, यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता में यूरोप के प्रतिनिधि शामिल नहीं

अबू धाबी,एजेंसी। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच दो दिन चलने वाली बातचीत आज यहां शुरू हो गई। इस त्रिपक्षीय बातचीत में यूरोप का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बातचीत की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान ने की। इसके बाद तीनों प्रतिनिधिमंडलों के राजनयिकों ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद नाह्यान बातचीत वाले कमरे से बाहर चले गए और चर्चा बंद दरवाजों के पीछे शुरू हुई।

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बंद कमरे में हुई शुरू हुई इस बातचीत से पहले रूस और अमेरिका के साथ यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बैठक में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हुए। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता का यह नया दौर है। ट्रंप प्रशासन लगभग पांच साल से चल रहे इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश में फिर से जुट गया है। उसने इसकी बिनाह पर मॉस्को को कई बड़ी रियायतें देने की घोषणा भी की है। यह बातचीत फरवरी के बाद पहली बार हो रही है। रूस की इच्छा थी कि यह वार्ता पूरी तरह से तीन पक्षों (अमेरिका, यूक्रेन और रूस) के बीच ही रहे। इसलिए यूरोप का कोई प्रतिनिधि बैठक में मौजूद नहीं है। हालांकि, कई यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नाटो और यूरोपीय संघ



के अधिकारी भी अलग-अलग बैठकों के लिए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में मौजूद हैं। बातचीत शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और वार्ताकार जेरेड कुशनर ने कहा, 'हम बातचीत के जरिए एक ऐसा समाधान खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्थायी शांति आ सके और एक संप्रभु, सुरक्षित और समृद्ध यूक्रेन के लिए हालात बन सकें।' अमेरिकी अधिकारियों ने इस रुख को दोहराते हुए कहा कि बातचीत युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक नई शुरुआत है। इसमें सुरक्षा गारंटी और युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा शामिल होगी। रूस की सिर्फ त्रिपक्षीय वार्ता की जिद पर यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा कि उन्हें ऐसे कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं कि मॉस्को ईमानदारी से बातचीत करने के लिए तैयार है। इस बीच, अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि शांति वार्ता के हिस्से के रूप में अमेरिका की ओर से सुरक्षा गारंटी दी जाएगी या नहीं, इसका फैसला ट्रंप ही करेंगे। एक अधिकारी के अनुसार बातचीत का नेतृत्व अमेरिका की ओर से कुशनर और मध्य पूर्व के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के विदेशी खुफिया प्रमुख और मुख्य वार्ताकार रुस्तम उमेरोव कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी तास के अनुसार रूस ने अपने प्रतिनिधिमंडल में उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव और मिखाइल गलुज़िन को भेजा है। क्रेमलिन के सहयोगी व्लादिमीर मेडिंस्की, सैन्य खुफिया प्रमुख इगोर कोस्त्युकोव और जनरल स्टाफ के सदस्य यूरी झिगारलोव्स्की भी बातचीत में शामिल हैं। यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार उमेरोव ने बैठक शुरू होने से पहले कहा कि ई 4 समूह (यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली) के प्रतिनिधि, साथ ही नाटो और यूरोपीय आयोग के अधिकारी भी अबू धाबी में मौजूद रहेंगे। उमेरोव ने कहा, 'हम अपने यूरोपीय साझेदारों के साथ अलग-अलग समन्वय बैठकें करेंगे।'

डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी जासूसी के आरोपों से घिरे एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग का बचाव किया

वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया ने चीन की खुफिया गतिविधियों के निशाने पर आए अपने सह संस्थापक और सीईओ जेन्सेन हुआंग के खिलाफ स्वतंत्र जांच शुरू की है। यह जांच उनके एलिस हुआंग नाम की एक चीनी बिजनेस एग्जीक्यूटिव से जुड़े होने के आरोपों के बाद सामने आई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि एलिस हुआंग चीन की मुख्य खुफिया एजेंसी 'मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी' के लिए काम करती थीं। एनवीडिया की जांच की घोषणा के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को जेन्सेन हुआंग को बेहतरीन इनसान बताते हुए बचाव किया है।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस की एक ब्रीफिंग के दौरान जेन्सेन हुआंग को 'बहुत ही बेहतरीन इंसान' बताया। उन्होंने कहा, 'एफबीआई किसी और मामले के सिलसिले में इसकी जांच कर रही है और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा।' ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने सोमवार को जेन्सेन हुआंग से बात करके उनका हाल-चाल जाना। उन्होंने कहा कि हुआंग ने बताया कि 'उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिलाकी बात हो रही है, वह एक जासूस है। हुआंग सेमीकंडक्टर क्षेत्र में दिग्गज माने जाते हैं। उनपर एक संदिग्ध चीनी महिला जासूस के साथ संबंध रखने का आरोप लगा है। ट्रंप ने हुआंग को 'बहुत ही बेहतरीन इंसान' बताया और उम्मीद जताई कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं पहुंचा होगा। ट्रंप ने कहा, 'जब मैंने इस बारे में सुना, तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन इंसान मानता हूं और उन्हें लंबे समय से जानता हूं। यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है—शायद वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी। उन्होंने यह सब एक चिप के जरिए हासिल किया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने बताया कि उन्होंने पहले हुआंग से बात कर पूछा कि क्या उन्हें उस महिला के चीनी खुफिया एजेंसियों से जुड़े होने की जानकारी थी। ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने कहा, 'मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह एक जासूस है। मुझे उनकी बात पर पूरा भरोसा है।' एनवीडिया के तकनीकी दबदबे का जिक्र करते हुए, ट्रंप ने कहा कि हुआंग की इंजीनियरिंग उपलब्ध दुनिया भर में बेजोड़ हैं। राष्ट्रपति ने कहा, 'आप देखिए, उनके पास एक ऐसी चिप है जो 10 साल आगे की तकनीक है।

इजराइल में नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह आज

यरुशलम। इजराइल की 26वीं नेसेट (संसद) का उद्घाटन सत्र और शपथ ग्रहण समारोह आज शुरू हो गया। समारोह में राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग, नेसेट स्पीकर अमीर ओहाना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 11:30 बजे (इजराइल के समय के अनुसार सुबह आठ बजे) हो गई है।

द यरुशलम पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार नवनिर्वाचित सांसदों को संसद के प्रवेश द्वार पर अपने कोट पर लगाने के लिए फूल दिया गया। नए सांसदों का स्वागत 'मिस्टर वेल' और 'मिसेज शगाल' नाम के दो रोबोट ने किया। इजराइल के समयानुसार दोपहर 3:20 बजे नेसेट प्लाजा में आधिकारिक समारोह शुरू होगा। ओहाना, राष्ट्रपति हर्ज़ोग का स्वागत करेंगे। नेसेट गार्ड राष्ट्रपति के सम्मान में एक औपचारिक परेड आयोजित करेंगे। इसमें आईडीएफ ऑर्केस्ट्रा तुरही (ट्रम्पेट) की धुन बजाएगा।

इसके बाद राष्ट्रपति का ध्वज फहराया जाएगा। फिर हर्ज़ोग और ओहाना 'ऑनर गार्ड' (सम्मान रक्षक दल) का निरीक्षण करेंगे। राष्ट्रपति नेसेट प्लाजा में स्थित इजराइल के शहीद सैनिकों के स्मारक और आतंकवादी हमलों के पीड़ितों की याद में बने स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। इसके बाद हर्ज़ोग और ओहाना नेसेट स्पीकर के कार्यालय के प्रवेश हॉल में जाएंगे, जहां राष्ट्रपति 'प्रेसिडेंट्स बुक' (राष्ट्रपति की पुस्तक) में हस्ताक्षर करेंगे। यह विशेष रूप से तैयार की गई पुस्तक है। इसमें इजराइल के राष्ट्रपति हर नई नेसेट के लिए संदेश लिखते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्लेनम (सदन) में प्रवेश करेंगे। नेसेट शपथ ग्रहण समारोह शाम 04 बजे शुरू होगा। हर्ज़ोग हथौड़ी (गेवल) को तीन बार मेज पर ठोंककर औपचारिक रूप से सत्र की शुरुआत करेंगे और फिर अपना संबोधन देंगे। इसके बाद वे ओहाना को पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित करेंगे और सत्र की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप देंगे। ओहाना के संबोधन के बाद सभी 120 सांसद बारी-बारी से शपथ लेंगे। ओहाना और नेतन्याहू भी सभा को संबोधित करेंगे। इजराइली गायक हारेल स्काट गीत प्रस्तुत करेंगे। समारोह में सबसे पहले दिवंगत सार्जेंट रीफ हारुश के पिता एवी हारुश इस समारोह में 'बुक ऑफ साल्म्स' (भजन संहिता) से 'साल्म 122' (भजन 122) का पाठ करेंगे।

नेपाल में 107 निर्वाचित पद खाली, स्थानीय स्तर पर सबसे ज्यादा 85 पद रिक्त

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल में जनप्रतिनिधियों के कुल 107 पद फिलहाल खाली हैं। इनमें स्थानीय स्तर के 85, प्रदेश सभाओं के 20 और राष्ट्रीय सभा के दो पद शामिल हैं। निर्वाचन आयोग के सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे के अनुसार, ज्यादातर पद स्थानीय और प्रांतीय जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि सभा चुनाव लड़ने के लिए अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने के कारण खाली हुए हैं। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए 20 जनवरी को उम्मीदवारों का नामांकन दर्ज किया गया था। इस्तीफा देने वालों में धरान उपमहानगरपालिका के मेयर हर्क साम्पांग भी शामिल हैं। उन्होंने सुनसरी-1 से प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उपमेयर ऐन्द्रविक्रम बेघा उपमहानगरपालिका का कामकाज संभाल रहे हैं।

इसी तरह भरतपुर महानगरपालिका की मेयर रेणु दाहाल, धुलिखेल नगरपालिका के मेयर अशोक ब्यान्जू, टीकापुर नगरपालिका के मेयर रामलाल डगौरा और कालीगण्डकी गांवपालिका के अध्यक्ष खिमबहादुर थापा ने भी संसदीय चुनाव लड़ने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इन पदों पर अब तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। कई प्रदेश सभा सदस्यों ने भी प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। इनमें काठमांडू-2 से सुनील केसी, सिंधुपालचोक-2 से युवराज दुलाल, बारा-4 से रहबर अंसारी, रूपन्देही-4 से कन्हैया बनिया और डडेलधुरा से तारा प्रसाद जोशी शामिल हैं। ये सभी प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा



मधेश प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों सरोज कुमार यादव और सतीश कुमार सिंह, बागमती प्रदेश सभा के सदस्य अमन मास्के, लुम्बिनी के कृष्णध्वज खड़का और सुदूरपश्चिम के प्रकाश बहादुर शाह ने भी संसदीय चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश सभा की सदस्यता छोड़ दी थी। उनके पद भी अब तक खाली हैं।

उपचुनाव के लिए कानूनी प्रावधान

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, 2017 के अनुसार, मेयर, उपमेयर और वॉर्ड अध्यक्ष जैसे पद खाली होने पर उपचुनाव कराया जा सकता है, बशर्ते संबंधित पदाधिकारी के कार्यकाल में एक वर्ष से अधिक समय बाकी हो। हालांकि, 13 मई 2022 को हुए स्थानीय चुनावों से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अब केवल करीब छह महीने शेष है। ऐसे में मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत स्थानीय स्तर पर खाली पदों के लिए उपचुनाव होने की संभावना कम है। वहीं, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, 2017 की धारा 68 के तहत किसी प्रदेश सभा सदस्य का पद खाली होने पर उसके कार्यकाल में छह महीने से अधिक समय शेष रहने की स्थिति में उपचुनाव कराया जा सकता है। 20 नवंबर 2022 को हुए चुनावों से निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यों का कार्यकाल अभी एक वर्ष से अधिक बाकी है। इसलिए सरकार और निर्वाचन आयोग यदि निर्णय लेते हैं तो प्रदेश सभा की खाली सीटों पर उपचुनाव कराया जा सकता है।

नेपालका स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट प्रबंधन पर जोर



काठमांडू,एजेंसी। नेपाल ने वैश्विक दूरसंचार व्यवस्था में अपने रणनीतिक हितों, विशेष रूप से रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट (उपग्रह कक्षाओं) के प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता से उठाया है। कतर की राजधानी दोहा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के पूर्णाधिकार सम्मेलन 2026 के दौरान नेपाल ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की।

नेपाल के सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमिल्सिना के नेतृत्व में नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने दोहा एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (डीईसीसी) में आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। दोहा स्थित नेपाली दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्री तिमिल्सिना ने सम्मेलन में शामिल देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों की औपचारिक बैठक में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मित्र देशों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो के निदेशक पद के फ्रांसीसी उम्मीदवार एरिक फोर्नियर ने मंत्री तिमिल्सिना से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात में रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट के प्रबंधन सहित उन विषयों पर चर्चा हुई, जो नेपाल के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। फोर्नियर ने इस पद के लिए अपनी कार्ययोजना, दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा मंत्री तिमिल्सिना ने ईरान के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री सत्तार हाशेमी और तंजानिया की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एंजेला जैस्मिन कैरुकी के साथ भी शिष्टाचार मुलाकात की। इन बैठकों में आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री तिमिल्सिना ने कतर सरकार की ओर से सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों और अन्य प्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज में भी हिस्सा लिया।

क्या है आईटीयू पूर्णाधिकार सम्मेलन?

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) का पूर्णाधिकार सम्मेलन वैश्विक दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी नीतियों, नियमों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने वाला एक प्रमुख मंच है। इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि एकत्रित होकर दूरसंचार क्षेत्र की भावी दिशा और वैश्विक प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करते हैं। 'एक साथ, एक कनेक्टेड डिजिटल भविष्य की ओर' थीम के तहत आयोजित यह सम्मेलन 9 नवंबर से शुरू हुआ है और 27 नवंबर तक चलेगा।

नेपाल संवत 1147 की धूम, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने दी शुभकामनाएं

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल संवत के नए वर्ष 1147 की आज देश में धूम है। विशेष रूप से नेवार समुदाय के लोग इस दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। नेपाल संवत देश का अपना मौलिक और विशिष्ट कैलेंडर है। इसकी शुरुआत 880 ईस्वी में लिच्छवि राजा राघवदेव के शासनकाल में शंखधर साख्वा ने की थी। उन्होंने लोगों को कर्ज से मुक्त कराया था और इसी ऐतिहासिक योगदान की स्मृति में नेपाल संवत की शुरुआत हुई थी। राष्ट्र और समाज के प्रति शंखधर साख्वा के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सरकार ने 18 नवंबर 1999 को उन्हें राष्ट्रीय विभूति घोषित किया था।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा कि पारंपरिक त्योहार समाज के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने का अवसर देते हैं। ये पर्व सामाजिक एकता, सद्भाव और सहिष्णुता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेपाल संवत 1147 (न्हूदँया भिंतुना) और म्ह: पूजा के अवसर पर जारी शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री शाह ने देश और विदेश में रहने वाले सभी नेपाली नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने नेपाल संवत को देश की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक चंद्र कैलेंडर का अभिन्न हिस्सा बताया। शाह ने राष्ट्रीय विभूति शंखधर साख्वा के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने नेवार समुदाय में प्रचलित म्ह: पूजा के सांस्कृतिक और



आध्यात्मिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह परंपरा व्यक्ति को आत्मसम्मान, आत्मबोध और आध्यात्मिक शुद्धि का संदेश देती है। इसके साथ ही यह पूर्वजों की विरासत को संरक्षित करने तथा समुदाय के भीतर सद्भाव और एकजुटता को बढ़ावा देने में भी मदद करती है। प्रधानमंत्री शाह ने गोवर्धन पूजा और गोरु तिहार के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन अवसरों पर कृषि कार्यों में बैलों और कृषि उपकरणों के योगदान को सम्मान देते हुए उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का संबंध हिंदू धार्मिक मान्यता से भी है। मान्यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने द्वारका के लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। उन्होंने पारंपरिक भैलो और देउसी गीतों तथा शुभकामनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये परंपराएं पड़ोसियों के बीच संबंधों को मजबूत करने और आपसी सद्भाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंत में प्रधानमंत्री ने इन सभी पर्वों के अवसर पर देशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की।

एक नजर

एनटीपीसी ने कोयला गैसीकरण योजना के दूसरे चरण में दिए दो आवेदन, तीसरा चरण भी हुआ शुरु

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण में सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने दो आवेदन दिए हैं। सरकार ने योजना का तीसरा चरण भी मंगलवार को शुरू कर दिया है, जिसके तहत पात्र कंपनियां 11 जनवरी, 2027 तक आवेदन कर सकेंगी। कोयला मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि एनटीपीसी की ओर से दिए गए दोनों आवेदनों में यूरिया, मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (डीएमई) के उत्पादन का प्रस्ताव है। इससे कोयला गैसीकरण के जरिये उर्वरक और रसायन जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की संभावनाएं सामने आती हैं। मंत्रालय ने बताया कि पहले दो चरणों में हासिल प्रगति को आगे बढ़ाते हुए कोयला मंत्रालय ने आज से योजना का तीसरा चरण आरम्भ किया है। इसके तहत पात्र संस्थाओं को देश में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पेश करने का एक और अवसर दिया गया है। तीसरे चरण के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी, 2027 है। मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई, 2026 को देश में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के विकास को गति देने के उद्देश्य से 37,500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय की सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी थी। कोयला मंत्रालय ने कहा कि सतही कोयला से तात्पर्य उस कोयले से है जो जमीन की सतह के बहुत करीब आमतौर पर 200 फीट या उससे कम गहराई पर स्थित होता है। इस कोयले को निकालने के लिए भूमिगत खदानों की आवश्यकता नहीं होती बल्कि सतही खनन तकनीक का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कोल गैसीफिकेशन एक ताप-रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें ठोस कोयले को सीधे जलाने के बजाय, सीमित मात्रा में ऑक्सीजन और भाप के साथ उच्च तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके गैस में बदला जाता है।

श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने 2026-27 की पहली छमाही में अर्जित की 21 फीसदी की ग्रोथ

नई दिल्ली,एजेंसी। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन करते हुए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (जीडीपीआई) में सालाना आधार पर 21 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने इस दौरान कुल 2,470.41 करोड़ रुपये का प्रीमियम अर्जित किया है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी (एसजीआई) ने अपने कारोबार के सभी प्रमुख क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के दम पर चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में भी अपनी तेज गति से बढ़ोतरी हासिल की। खास बात यह है कि कंपनी ने कारोबार के प्रमुख क्षेत्रों में पूरी सामान्य बीमा इंडस्ट्री के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के अनुसार कंपनी की ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम (जीडीपी) आय वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 2,470.41 करोड़ रुपए हो गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 2,045.46 करोड़ रुपये रही थी। इस दौरान जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ 9 फीसदी तक सीमित रही। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने बताया कि पहली तिमाही में शुरू हुई तेज वृद्धि दर दूसरी तिमाही में भी जारी रही। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनी की जीडीपी 18.94 फीसदी बढ़कर 1,290.59 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष इसी तिमाही में यह 1,085.08 करोड़ रुपये ही थी। इस दौरान कंपनी की वृद्धि दर भी पूरे सामान्य बीमा क्षेत्र की 6.97 फीसदी की रफ्तार से काफी अधिक रही। कंपनी ने बताया कि कारोबार का सबसे बड़ा हिस्सा मोटर इंश्योरेंस से ही आता है। इसने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में अर्जित बढ़ोतरी में सबसे अहम भूमिका निभाई। मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम पिछले साल के 1,002 करोड़ रुपए से 19 फीसदी बढ़कर 1,189 करोड़ रुपये हो गया। प्रीमियम में इस तेज बढ़ोतरी के साथ ही कंपनी ने अपने मुनाफे वाले कारोबार को बढ़ाने पर भी खास ध्यान दिया। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा (पीएटी) सालाना आधार पर 7.28 फीसदी बढ़कर 289.04 करोड़ रुपये हो गया।

बॉम्बे हाई कोर्ट का गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार

मुंबई,एजेंसी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां की गिरगांव चौपाटी पर समुद्र तट के पास छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि धर्म का पालन करने का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। मिथिला छठ पूजा संघ की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस अद्वैत सेठना और जस्टिस रंजितसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने कहा कि संविधान में निर्धारित विभिन्न नियंत्रणों एवं संतुलन के प्रावधानों का सभी को पालन करना होगा। हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 25 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें नि:संदेह अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका पालन करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। हालांकि, यह स्वतंत्रता संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। दूसरे शब्दों में संविधान में कुछ नियंत्रण और संतुलन निर्धारित किए गए, जिनका पालन करना आवश्यक है।



मिथिला छठ पूजा संघ ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के आयोजन के लिए दो दिनों तक अस्थायी मंच बनाने की अनुमति मांगी थी। संघ के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने इस साल सितंबर में मंच बनाने की अनुमति देने से इनकार किया था। पुलिस ने अनुमति देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट के 1998 के एक आदेश का हवाला दिया था। उसमें कहा गया कि गिरगांव चौपाटी पर गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वर्ष 1998 की कार्यवाही में हाई कोर्ट ने एक निगरानी समिति गठित की थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि चौपाटी क्षेत्रों में किसी भी आयोजन की अनुमति मांगने वाली याचिका में इस समिति को अनिवार्य रूप से पक्षकार बनाया जाए। मौजूदा मामले में कोर्ट ने पाया कि याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि निगरानी समिति को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। इस आधार पर कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार किया।

सर्राफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी के भाव में बदलाव नहीं

नई दिल्ली,एजेंसी। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में उछाल आने के कारण देश के अलग अलग सर्राफा बाजार में सोना 970 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,050 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। दूसरी ओर, चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह चमकीली धातु आज भी सोमवार के भाव पर ही कारोबार कर रही है। कीमत में बदलाव होने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,44,610 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,44,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,32,560 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,32,710 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में आज कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण यह चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज भी 2,04,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,44,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,710 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,44,610 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,44,660 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,610 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,44,610 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,32,560 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,44,610 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,32,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,44,760 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,710 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,32,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,32,710 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जब हमारे भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण भी जरूर मुस्कुराएंगे : मोहन यादव

वाराणसी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का करीब 5 हजार साल पुराना इतिहास हम सभी को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन सिखाता है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद इंसान को अपना हौसला बनाए रखना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए और हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अन्नकूट पर्व पर गोवर्धन पूजा समिति की ओर से नमोघाट पर आयोजित गोवर्धन पूजनोत्सव को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के विभिन्न स्वरूपों में गोवर्धन का स्वरूप हमें खास संदेश देता है। ये प्रकृति के पूजन और उसके संरक्षण की प्रेरणा देता है। भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। ये प्रसंग हमें बताता है अहंकार का अंत निश्चित है और प्रकृति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। भगवान कृष्ण और सुदामा के दोस्ती का उल्लेख कर कहा कि दोस्ती हो जाए तो उसे जीवनभर नहीं भूलना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण ने सुदामा के साथ अपनी मित्रता के जरिए दुनिया को इसका उदाहरण दिया है।

जब हमारे भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण भी जरूर मुस्कुराएंगेसमारोह में उन्होंने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि परमात्मा ने समय बदला है। जब हमारे भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण भी जरूर मुस्कुराएंगे। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। आने वाला समय और आनंदमय होगा। यह पर्व इंद्र का घमंड चूर करने और प्रकृति के प्रति प्रेम व संरक्षण का संदेश देता है। समारोह में उन्होंने कहा कि सत्ता आती-जाती रहती है, लेकिन मित्रता का महत्व हमेशा बना रहता है। दोस्ती में मदद भी इतनी दिल खोलकर करनी चाहिए कि उससे खुद को आनंद और संतोष मिले।

समारोह में गोवर्धन पूजा समिति के पदाधिकारियों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवनाथ यादव और डीपी यादव के संबोधन की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारा भाषण कभी-कभी अटपटा हो सकता है, लेकिन शिवनाथ यादव ने बेहद शानदार और धाराप्रवाह ढंग से अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यादव समाज में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले दस प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को 'गोवर्धन श्री सम्मान' से सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में न्यायिक क्षेत्र में पूर्व न्यायाधीश महेंद्र सिंह यादव, चिकित्सा क्षेत्र में डॉ. कुमार भास्कर, खेल के क्षेत्र में शिखा यादव, योग शिक्षा में प्रो. संबित भूषण, विज्ञान एवं अनुसंधान में अमित यादव तथा विधि के क्षेत्र में देवी प्रसाद यादव सहित अन्य लोग शामिल रहे।

श्रद्धा, अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक बनेगा गढ़मुक्तेश्वर व तिगरी मेला: मुख्यमंत्री

लखनऊ,एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला गुढ़मुक्तेश्वर तथा तिगरी मेला की तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा की। इस दौरान मेरठ, बरेली, अमरोहा, हापुड़, मुरादाबाद आदि मंडलों/जनपदों के प्रशासन व पुलिस विभाग के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध तैयारियों का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 'वेस्टर्न यूपी का मिनी कुम्भ' यह मेला श्रद्धा, अनुशासन व स्वच्छता का प्रतीक बनेगा। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुमग यातायात व स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम कर लें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 से 26 नवंबर तक लगने वाले इस मेले में 25 से 30 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे। 24 नवंबर को मुख्य स्नान पर्व होगा। यहां आस्था, परंपरा व सुव्यवस्था का संगम होगा, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से कर ली जाएं। ऐसे में यहां सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कतई न हो। मुख्यमंत्री ने शासन के गृह, लोकनिर्माण विभाग, परिवहन, सिंचाई, नगर विकास, ऊर्जा, पंचायती राज, स्वास्थ्य समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को मेला प्रारंभ से पहले निरीक्षण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेले के कमांड एरिया में शराब व नशे की वस्तुओं की बिक्री कतई न हो और न ही आस्था के विपरीत कोई आचरण हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि घाटों पर स्नान के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। नदी को आवश्यक्तानुसार चैनलाइज किया जाए। हर घाट पर जल की उपलब्धता रहे। पर्याप्त स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि यहां सीएचसी स्तर के अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जाएं। पर्याप्त मैनपावर, एंबुलेंस समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें। विद्युत की नियमित आपूर्ति व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें दोनों तरफ तैनात की जाएं। मेले से पहले एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी स्तर के अधिकारी पुलिस बल की काउंसिलिंग कर लें। पुलिसकर्मी रील बनाने की प्रवृत्ति से दूर रहें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वॉच टावर, फायर डेंटर, सीसीटीवी, यातायात-पार्किंग प्रबंधन, डायवर्जन आदि की समुचित व्यवस्था की जाए।



मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेले में खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को मंच दिया जाए। मंच पर सभ्य कार्यक्रम ही हों, आस्था के विपरीत कोई भी कार्यक्रम न हो। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर हर आयुवर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने पर्यटन-संस्कृति विभाग को निर्देशित किया कि मेले में श्रीमद्भागवत कथा, रासलीला, रामलीला, भगवान शिव से जुड़े आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। लेजर शो, ड्रोन शो आदि भी कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाए। बच्चों की स्लोगन, भाषण, वाद-विवाद, निबंध आदि प्रतियोगिताएं कराई जाएं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर धार्मिक व राष्ट्रभक्ति गीत बजाए जाएं और जनता के बीच अच्छे कार्यों को पहुंचाया जाए। शासन की योजनाओं व उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किया जाए।

बिहार कैबिनेट के 32 प्रस्तावों पर मुहर, सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा

पटना,एजेंसी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि समेत कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। छठ पर्व से पहले राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए विभिन्न वेतनमानों के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय लिया। इसके साथ ही शिक्षा, ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन और तकनीक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सप्तम केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पंचम केंद्रीय वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत तथा षष्टम केंद्रीय वेतनमान के तहत 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी गई है। सरकार के इस फैसले से राज्य के विभिन्न वेतनमानों के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

कैबिनेट ने मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना पर 254 करोड़ 57 लाख 38 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026 को भी मंजूरी दी गई है। राज्य में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 'बिहार



की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' शुरू करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक इस योजना के माध्यम से 2,100 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फैलोशिप योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक लागू करने के लिए 126 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1,399 करोड़ 60 लाख 28 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से योजना के तहत चयनित ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट ने बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन परियोजना के लिए 4,572.53 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय को मंजूरी दी है। इसके अलावा हाजीपुर में बस स्टैंड निर्माण के लिए 9 एकड़ 73 डिसमिल जमीन के अधिग्रहण पर 44 करोड़ 52 लाख 44 हजार रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। राज्य में इको टूरिज्म और पार्कों के विकास से जुड़ी 11 योजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत संचालित करने की भी मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को कम करने के उद्देश्य से बिहार भवन विधि, 2026 को स्वीकृति दी है। इससे भवन निर्माण की अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने का लक्ष्य है। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मिशन की स्थापना के बाद इसके संचालन में अग्रणी उद्योग संस्थानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क, सिंगापुर का चयन किया गया है। राज्य की 59 जेलों में प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन के तहत 159 कियोस्क का संचालन पांच वर्षों तक ओपेक्स मॉडल पर किया जाएगा। इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को 8 करोड़ 25 लाख 20 हजार रुपये देने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू-अर्जन निदेशालय के तहत विभिन्न श्रेणियों के कुल 438 स्थायी पदों के प्रत्यर्पण और 342 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। वित्त विभाग में संविदा पर कार्यरत बजट सलाहकार ओमप्रकाश झा की संविदा अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग संशोधन नियमावली, 2026 और बिहार आयुष मिश्रक नियमावली, 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्वाचन कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त वाहनों के लंबित दायित्वों समेत आवश्यक भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 2,247 करोड़ 53 लाख 82 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस तरह कैबिनेट की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी देकर राज्य सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने के साथ-साथ आधारभूत संरचना, ग्रामीण आवास, शिक्षा, उद्यमिता, पर्यटन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई फैसले किए।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप से बिहार में बंधक बनाए गए झारखंड के आठ श्रमिक मुक्त

गिरिडीह,एजेंसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बाद झारखंड के गिरिडीह जिले के आठ श्रमिकों को बिहार के गयाजी में बंधक बनाए जाने की स्थिति से मुक्त करा लिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गिरिडीह जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी श्रमिकों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। मंगलवार को उनकी घर वापसी हुई। सभी श्रमिक पीरटांड़ प्रखंड की हरलाडीह पंचायत के अलग-अलग गांवों के निवासी हैं।



जानकारी के अनुसार, आठों श्रमिक रोजगार और आजीविका की तलाश में बिहार के गयाजी जिले गए थे। वहां वे गयाजी सदर क्षेत्र स्थित एक बोरवेल कंपनी में काम कर रहे थे। आरोप है कि कंपनी के मालिक ने पिछले सप्ताह उनके मोबाइल फोन छीन लिए थे। इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और मजदूरी का भुगतान भी बंद कर दिया गया। श्रमिकों को जबरन रोककर रखा गया था। पीरटांड़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) मनोज मरांडी ने बताया कि श्रमिकों से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में आया। कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों के मोबाइल फोन छीन लिए गए थे। इसके बावजूद उन्होंने किसी तरह दूसरे मोबाइल की मदद से अपनी स्थिति का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला प्रशासन और सरकार तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को तत्काल श्रमिकों को मुक्त कराने का निर्देश दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई शुरू की। प्रशासनिक पहल के बाद सभी आठ श्रमिकों को मुक्त कराया गया और मंगलवार को उनके गृह क्षेत्र पहुंचाया गया। सकुशल लौटे श्रमिकों में सुनील मुर्मू, सुखू टुडू, सुरेंद्र मुर्मू, राजू बास्के, करमू टुडू, बबलू मरांडी, दिनेश सोरेन और रंजीत मुर्मू शामिल हैं। इनमें सुनील मुर्मू, सुखू टुडू, सुरेंद्र मुर्मू, दिनेश सोरेन और रंजीत मुर्मू बरवाडीह गांव के निवासी हैं। राजू बास्के भेलवाडीह, करमू टुडू जरकाई और बबलू मरांडी शहरपुरा गांव के रहने वाले हैं। श्रमिकों की सुरक्षित वापसी पर स्थानीय लोगों ने राहत जताई। बीडीओ मनोज मरांडी ने स्वयं श्रमिकों का स्वागत किया और उन्हें घर पहुंचाने की व्यवस्था की। लंबे समय बाद परिवार के बीच लौटने पर श्रमिकों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)